लखनऊ
रविवार, 2 अगस्त , 2026
वर्ष : 11 | अंक: 334
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8
UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक
आर्यावर्त क्रांति

क्रोध एक ऐसा तेज़ाब है, जो उस पात्र को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है जिसमें वह रखा जाता है।

TODAY WEATHER

DAY	NIGHT
32°	28°
Hi	Low

भोगपुरम एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित, पीएम मोदी बोले- युवाओं के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (1 अगस्त)को आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने विजयनगरम जिले के भोगपुरम में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 17900 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद रहे। यह आंध्र प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन की शुरूआत पीएम ने भारत मां की जयकारे के साथ की। पीएम ने कहा कि अल्लूरी सीताराम

राजू जी ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि आज का दिन आंध्र प्रदेश के लिए बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है।

'पहले एक ही परिवार के नाम पर होते थेनाम'

पीएम ने कहा, पहले जब हवाई अड्डे बनते थे, तो उनके नाम एक ही परिवार के नाम पर होते थे। हमने इस परंपरा को बदला। उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। वहीं पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने ये निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में देश में लगातार विकास हो रहा है।

60 लाख यात्रियों की क्षमता

पहले चरण में इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों की क्षमता के अनुरूप तैयार किया गया है, जबकि मास्टर प्लान के तहत भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर प्रतिवर्ष चार करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की योजना है। भोगपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट है। यहां से 17 अगस्त को फ्लाइट ऑपरेशन्स की शुरुआत होगी।

'आंध्र प्रदेश के युवाओं ने पुरी दुनिया में अपना डंका बजाया'

पीएम ने कहा कि आज एविएशन, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट राज्य के विकास में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के युवाओं ने पुरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। उन्होंने कहा कि आज का यह आयोजन नया इतिहास, नए रिकॉर्ड इसे रचने का भी है। उन्होंने आज एक तरफ विकास के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो दूसरी तरफढिमसा नृत्स का सांस्कृति रिकॉर्ड भी रचा गया है।

घास काटकर लौट रही तीन मासूम बच्चियां उफनती नहर में डूबीं, 12 घंटे बाद मिले शव, गांव में पसरा मातम

आर्यावर्त क्रांति

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां दुबौली गांव के पास एक ही परिवार की तीन मासूम बच्चियों की गहरे पानी में डूबने से खौफनाक मौत हो गई। हंसती-खेलती ये बच्चियां खेत से घास काटकर अपने घर लौट रही थीं, तभी काल ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शनिवार सुबह तीनों बच्चियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसके बाद पूरे गांव में मातम का सन्नाटा पसर गया है।

जानकारी के मुताबिक, यह घटना स्थानीय थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के पास स्थित सिधरिया ड्रेन (नहर) की है। शुक्रवार की शाम गांव के रहने वाले शंभू की दो बेटियां, 10 वर्षीय सपना और 8 वर्षीय छोटी, रंजीत की 12 वर्षीय बेटी कुंचन के साथ खेत गई थीं। तीनों बच्चियां खेत से घास काटकर वापस घर की तरफ आ रही थीं। इसी दौरान बभनौली गांव के पास सिधरिया ड्रेन की पुलिया पर वे कुछ पल आराम करने के लिए रुकीं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वहां बैठते ही अचानक बच्चियों का संतुलन बिगड़ गया और वे तेज बहाव वाली नहर में जा गिरीं। पानी का बहाव इतना तेज था कि पलक झपकते ही तीनों लहरों में समा गईं। मौत के इस तांडव के वक्त सपना का 10 साल का छोटा भाई कलुआ भी उनके साथ मौजूद था। अपनी बहनों को पानी की तेज धारा में बहता देख वह बुरी तरह घबरा गया। वह बदहवास हालत में रोते-चिल्लाते

संक्षेप

रास्ते में खत्म हो गई एंबुलेंस की ऑक्सीजन, मां की गोद में तड़प-तड़प कर निकल गई 21 वर्षीय बेटे की जान

मुंबई, एजेंसी। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलती एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है। कोई भी राज्य या सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि उसकी पहचान ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था से हो, जहां एक बेबस मरीज दम तोड़ दे। लेकिन मंडला जिले में ऐसा ही हुआ है। यहां एक 21 साल के जवान बेटे ने एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण अपनी ही मां की गोद में तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक अमले और एंबुलेंस सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रूह कंपा देने वाला मामला 27 जुलाई का है, लेकिन यह तब सुर्खियों में आया जब 31 जुलाई को इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मजबूर मां-बाप अपने तड़पते हुए बच्चे को गोद में लिए बैठे हैं। एंबुलेंस के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वह नौजवान एक-एक सांस के लिए बुरी तरह छटपटा रहा है। जीवन और मौत के बीच झूलते हुए अंततः उस युवक ने अपनी मां की बांहों में ही हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मृतक युवक की पहचान अजीत बरैया के रूप में हुई है। वह बम्हनी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुनेहरा गांव का रहने वाला था।

एविएशन सेक्टर को मिलेगी नई उड़ान, देश में खुलेंगे 11 नए फ्लाइंग स्कूल; 30 हजार पायलटों की जरूरत

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे एविएशन सेक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पायलटों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से देशभर में 11 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन शुरू किए जाएंगे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (र्एढ्ढ) ने फरवरी 2026 में जारी ई-टेंडर के तहत सात एयरपोर्ट पर 11 नए एफटीओ स्लॉट की टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सिविल एविएशन मंत्रालय के अनुसार, अगले 10 वर्षों में देश को लगभग 30 से 31 हजार अतिरिक्त पायलटों की आवश्यकता होगी। वहीं, अगले पांच वर्षों में भारतीय एयरलाइंस अपने बेड़े में करीब 500 नए विमान शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा देश में लगभग 50 नए एयरपोर्ट विकसित होने की भी संभावना है। एविएशन सेक्टर की तेज रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया अगले 18 महीनों में अपने बेड़े में 50 से 60 नए विमान शामिल करने की तैयारी कर रही है। अप्रैल 2026 तक देश में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त 41 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन 63 फ्लाइंग बेस से संचालित हो रहे हैं। नए एफटीओ शुरू होने से देश में पायलट प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ेगी और भारतीय छात्रों की विदेश जाकर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता भी कम होगी। इन 11 नए एफटीओ में शुरुआती चरण में 60 से 70 प्रशिक्षण विमान शामिल किए जाने की संभावना है।

पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाली लड़की ने मांगी माफी
'मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि नजरें भी नहीं उठा पा रही'

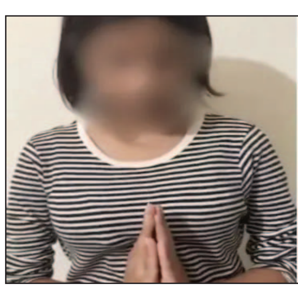

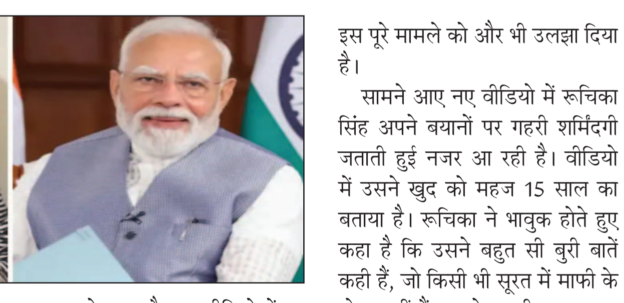

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब एक नया मोड़ ले चुका है। इस मामले में विवादों में घिरी रूचिका सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में वह अपने किए पर भारी पछतावा जताते हुए पूरे देश से माफी मांग रही है। रूचिका का कहना है कि उसने जो भी किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उसकी उम्र और उसकी पिछली पहचान को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसने इस पूरे मामले को और भी उलझा दिया है।

सामने आए नए वीडियो में रूचिका सिंह अपने बयानों पर गहरी शर्मिंदगी जताती हुई नजर आ रही है। वीडियो में उसने खुद को महज 15 साल का बताया है। रूचिका ने भावुक होते हुए कहा है कि उसने बहुत सी बुरी बातें कही हैं, जो किसी भी सूरत में माफी के योग्य नहीं हैं। उसने अपनी इस हरकत को 'पहली और आखिरी गलती' करार देते हुए देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील की है। रूचिका का कहना है कि उसे अपने किए पर इतनी शर्म आ रही है कि वह खुद को आइने में भी नहीं देख पा रही है, इसलिए उसे इस भारी भूल के लिए माफ कर दिया जाए।

कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला : 'विक्टिम कार्ड' खेलने का लगाया आरोप, माफी की मांग की

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन युवाओं को माफ करने की बात कहकर 'विक्टिम कार्ड' खेल रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपशब्द कहे थे। विपक्षी पार्टी ने मांग की कि प्रधानमंत्री प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई 'बर्बर कार्रवाई' और पेपर लीक के कारण युवाओं को हुई परेशानी के लिए माफी मांगें। विपक्षी पार्टी ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री की 'इंस्टाग्राम सभाएं' अब किसी को प्रभावित नहीं कर रही हैं। उन्होंने इसे 'अत्यधिक आत्ममुग्धता' का उदाहरण बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, बीती रात प्रधानमंत्री ने आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया है। यह देश और उन युवाओं का अपमान है, जिन्होंने उनकी सरकार के दौरान पीड़ा झेली है और जो पूरी तरह न्यायोचित रूप से उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकतीं। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा, खुद को गैर-जैविक बताने वाले प्रधानमंत्री को विक्टिम कार्ड (खुद को पीड़ित दिखाना) खेलना पसंद है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि वह अपने पूर्ववर्तियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए वे न केवल अपनी सार्वजनिक सभाओं में, बल्कि संसद के भीतर भी बार-बार झूठ फैलाते हैं। संसद के भीतर और बाहर अपशब्द कहने वालों की पूरी फौज को खुली छूट देते हैं और उन्हें पूरा संरक्षण भी प्रदान करते हैं।

वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि जंतर-मंतर पर उनकी दिवंगत मां को भी 'अपशब्द' कहे गए। उन्होंने यह भी कहा कि 'हमारी बेटियों' ने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने 'भटके हुए बच्चों' को माफ करने की बात कही।

संसद में 'पुजारी' बनकर बुरे फंसे पप्पू यादव, रामलला के अपमान पर एफआईआर दर्ज, स्पीकर भी हुए सख्त

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का संसद परिसर में किया गया अनोखा प्रदर्शन अब उनके ही गले की फांस बन गया है। राम मंदिर निर्माण के चंदे में कथित गबन का विरोध जताने के लिए उन्होंने जो 'नुक्कड़ नाटक' किया, उसने एक बड़े सियासी और कानूनी विवाद को जन्म दे दिया है। प्रदर्शन के दौरान भगवान राम की तस्वीर के कथित अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे ड्रामे के बाद अब लोकसभा सचिवालय भी सख्त कार्रवाई के मूड पप्पू यादव के खिलाफ यह शिकायत सूर्य मैथिल नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है

कि संसद परिसर के बाहर हुए इस नाटकीय प्रदर्शन में भगवान रामलला विराजमान की तस्वीर को पैरों के नीचे रखा गया, जिससे देशभर के सनातन धर्म प्रेमियों की भावनाएं गहरी तरह से आहत हुई हैं। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि पप्पू यादव के इस विवादित प्रदर्शन को राहुल गांधी, डिंपल यादव और अवधेश प्रसाद सहित 'इंडी' गठबंधन के कई बड़े सांसदों का मूक समर्थन हासिल था।

पीएम आवास तक निकालेंगे मार्च, ई-20 पेट्रोल के खिलाफ आप का टाउनहॉल

नई दिल्ली, एजेंसी। ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी शनिवार को नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई-20 का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी ने बताया कि दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में इस टाउनहॉल में लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़कर अपने अनुभव और सुझाव रखे।

आप ने दावा किया कि उनके कार्यक्रम में देश भर से 6 लाख लोग जुड़े। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत प्रधानमंत्री की आवाज निकालने वाले कलाकार श्याम रंगीला के अलावा यूट्यूबर मनीष कश्यप भी शामिल हुए।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, ₹कभी वे कहते हैं कि ई20 अच्छा है

और कभी कहते हैं कि E20 बुरा है। एक मंत्रालय कहता है कि E20 से 2-5% का फ़र्क पड़ता है, तो दूसरा मंत्रालय 4% की बात करता है। यानी, उन्होंने कोई स्टडी नहीं की। उन्होंने इसे जबरदस्ती लागू किया है। गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज कम हो रहा है। सरकार लोगों पर इसे क्यों थोप रही है? इसमें सरकार का क्या फायदा है? ई20 पेट्रोल अच्छा नहीं है।'

ईपीएफओ के निवेश घोटाले मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मिली लिखित शिकायत के आधार पर शुक्रवार (31 जुलाई) को मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL), उसके पूर्व चेयरमैन अनिल डी। अंबानी, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार जैसे अपराधों के जरिए ईपीएफओ को 1,007.55 करोड़ का गलत वित्तीय नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा 808.67 करोड़ की ब्याज देनदारी भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार कुल कथित नुकसान 1,816.22 करोड़ का बताया गया है। सीबीआई के मुताबिक , वर्ष 2013 और 2014 के दौरान रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी किए थे। इनमें ईपीएफओ ने रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड सहित चार पोर्टफोलियो मैनेजरों के माध्यम से 2,500 करोड़ का निवेश किया था। इन एनसीडी की परिपक्वता अवधि वर्ष 2023 और 2024 में थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन और धन के कथित दुरुपयोग (फंड डायवर्जन) में संलिप्त होकर ऐसी स्थिति पैदा की, जिसके कारण रिलायंस कैपिटल लिमिटेड एनसीडी का भुगतान (रिडेम्प्शन) करने में विफल रही।

आवारा पशुओं से हों हादसे तो मिले मुआवजा... सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी दुर्घटनाओं में मुआवजे के भुगतान के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश भी दिया। जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कई निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इन पशुओं के मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पशु हर रोज दिन खत्म होने पर अपने रहने वाले या बताए गए आवास पर वास लौट आएं।

पीठ ने कहा, सभी राज्य जिन्होंने मवेशियों से संबंधित कानून बनाए हैं, उन्हें अक्षरशः और तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने

चाहिए। दोनों श्रेणियों – पैदल यात्री या वाहन चालक के मामलों में पशुओं के वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजे के भुगतान के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। या फिर सक्षम प्राधिकारी की तरफ से उचित समझे जाने वाले नियमों को शामिल किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये फैसला लिया?

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पशुओं की टैगिंग अनिवार्य किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे उनकी निगरानी करने, उनकी दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने, पशु चिकित्सा जांच और टीकाकरण से जुड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये निर्देश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए आये। हाई कोर्ट ने महिला को मिलने वाला 29 ।32 लाख रुपये का मुआवजा रद्द कर दिया था। महिला के पति को सड़क पर चलते समय एक आवारा सांड ने टक्कर मार दी थी और सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद महिला ने पर्याप्त मुआवजे की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। एकल-न्यायाधीश पीठ ने मृतक की आय, आयु और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे के अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को लागू करके मुआवजे का आकलन किया और मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया।

किश्तवाड़ में बादल फटने से कई वाहन बहे, शोपियां में भी स्थिति खराब, हालात पर सरकार की नजर

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में शनिवार तड़के करीब 2:30 बजे बादल फटने की घटना हुई। घटना के बाद इलाके में अचानक आई तेज बाढ़ के कारण कई गाड़ियां बह गईं। वहीं संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, नुकसान का सही आकलन अभी किया जा रहा है। राहत की बात ये है कि अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

घटना के बाद एहतियात के तौर पर चतरू-किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इससे जुड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर

किया। उन्होंने कहा कि आज सुबह-सुबह छतरू इलाके में बादल फटने की खबर मिलने के बाद, मैंने किश्तवाड़ के DC पंकज कुमार शर्मा से बात की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुछ कमर्शियल दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा।

स्थानीय निवासियों को भरोसा दिलाने के लिए यह बताना ज़रूरी है कि पिछले साल चसोती में बादल फटने की घटना के बाद, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किश्तवाड़ और मछैल में दो अत्याधुनिक "अर्ली वार्निंग सिस्टम" (EWS) लगाए हैं। इसके अलावा, पाडर इलाके में एक "ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन" (AWS) भी लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

रेलवे ने डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग बंद किया, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। रेल पुलों के आसपास वाले पैदल पुल और मार्गों को बंद करने का क्रम जारी है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को रेल पुल संख्या 183 के नीचे स्थित डोमिनगढ़–डोहरिया मार्ग को भी बंद कर दिया। गोरखपुर पश्चिम के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) हिरामन के नेतृत्व में रेलकर्मियों की टीम ने मार्ग पर गड्ढा खोदवा दिया। साथ ही बैरिकेडिंग (लोहे का बैरियर) भी कर दी। जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मार्ग बंद करने का विरोध किया। नाराजगी जताते हुए लोगों ने कहा कि रास्ता बंद होने से 20 गांव के लोगों का आवागमन प्रभावित होगा।

सूचना पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। रेलवे के एसएसई और पुलिस ने लोगों को समझाकर वापस भेजा। एसएसई ने बताया कि रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश पर मार्ग बंद किया गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि डोमिनगढ़-डोहरिया मार्ग से डोहरिया बाजार, सिसई, जंगल कौडिया होते हुए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर तक आवागमन होता है। कालेसर जीरो प्वाइंट के रास्ते लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग का उपयोग करते है।

इस मार्ग के बंद होने से लोगों को घूमकर गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होगी। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन से मार्ग बंद करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा आमजन की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

पहले से बंद किए जा चुके हैं तीन पैदल पुल

रेलवे ने राप्ती नदी पर बने रेल पुल संख्या 184 के सर्विस पाथवे (पैदल पुल), डोमिनगढ़-जगतबेला रेलखण्ड पर स्थित रेलवे पुल संख्या 182 (ककरा नदी के ऊपर) तथा रेलवे पुल संख्या 183 (रोहिन नदी के ऊपर) के सर्विस पाथवे (पैदल पुल) पहले ही बंद कर दिया है। तीनों पाथ वे पर रेलवे प्रशासन ने अवरोधक लगाकर अनधिकृत आवागन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

अब गोरखपुर जंक्शन और कैंट स्टेशन के बीच रामगढ़ताल पर बने पाथवे को बंद करने की तैयारी है। जनविरोध के चलते अभी बंद नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि रेलवे पुलों के पास बने पाथवे रेलवे ट्रैक तथा रेलवे पुल के अनुरक्षण कार्य के लिए रेलवे कर्मचारियों के आवागमन के लिए बनाए गए हैं। जिसे आवश्यकता अनुसार ट्रैकमैन, कीमैन आदि तथा ट्रेन में कार्यरत लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर आदि कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

अमहट मंडी में गंदगी और मलबे का अंबार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अमहट मंडी रोड स्थित सिटी मंडी की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पूरे परिसर में जगह-जगह कचरा और कीचड़ फैला हुआ है। मंडी डायरेक्टर इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर हटवाया गया मलबा भी महीनो बीत जाने के बाद अब तक नहीं हटाया गया है। मलबा आज भी मंडी में पड़ा हुआ है और बड़ी जगह को कब्जाए हुए है।

व्यापारियों का आरोप है कि मंडी प्रशासन की लापरवाही और शिथिलता के कारण ही मंडी की यह दुर्दशा है। व्यापारियों के अनुसार मंडी में हर महीने की 1 तारीख को बंदी इसलिए रखी जाती है ताकि परिसर की साफ-सफाई और अवैध अतिक्रमण हटाया जा सके। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह कार्य भी कागजों तक ही सीमित रह गया है। व्यापारियों ने मांग की है कि मंडी में अवैध रूप से पड़े सभी मलबे और अन्य सामान को तत्काल हटाया जाए। उनका कहना है कि 30 वर्षों से एक ही जमीन अधिकारी इसी पद पर तैनात हैं। प्रमोशन के बाद भी उनका तबादला नहीं किया गया। स्थानीय लोगों से मधुर संबंध होने के कारण मंडी की व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं चल पा रही हैं। व्यापारियों ने उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर मंडी की व्यवस्था सुधारने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई और अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो व्यापारी कोर्ट का सहारा लेने को मजबूर होंगे।

राजकीय पशु चिकित्सालय बल्दीराय में सुविधाओं का अभाव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। तहसील मुख्यालय स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का खामियाजा पशुपालकों और बीमार पशुओं को भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सालय परिसर में बड़े पशुओं के उपचार के लिए कई दशक पहले बनाया गया कैटल क्रश (अड़गड़ा) साफ-सफाई अभियान के दौरान गिरा दिया गया था। उस समय जिम्मेदार लोगो ने जल्द ही इसे दोबारा बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण नहीं कराया गया।

कैटल क्रश के अभाव में बड़े पशुओं को सुरक्षित तरीके से बांधकर उनका उपचार करना संभव नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप दूर-दराज गांवों से अपने बीमार पशुओं को लेकर आने वाले पशुपालकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। इससे पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शासन पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं के बेहतर उपचार के लिए लगातार योजनाएं चला रहा है, लेकिन बल्दीराय राजकीय पशु चिकित्सालय में बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अस्पताल में जल्द से जल्द नया कैटल क्रश बनवाया जाए ताकि बीमार पशुओं का उपचार सुचारु रूप से हो सके और पशुपालकों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग से शीघ्र कार्रवाई कर चिकित्सालय की आवश्यक सुविधाएं बहाल कराने की मांग की है।

शाहजहांपुर में 9 साल की बच्ची से की दरिंदगी, 5 नाबालिग लड़कों पर लगा आरोप, लुका–छिपी खेल रहे थे सभी

आर्यावर्त संवाददाता

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले स्थित तिलहर थाना क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और सामाजिक ताने-बाने को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां बख्तियारपुर गांव में प्राइमरी स्कूल के पास खेल रहे बच्चों के बीच हुई एक घटना के बाद 9 वर्षीय मासूम बच्ची के माता-पिता ने थाने पहुँचकर 5 नाबालिगों के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। घटना के बाद पुलिस ने सभी नाबालिग आरोपियों को उनके परिजनों के साथ थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गांव के प्राइमरी स्कूल के पास करीब आधा दर्जन बच्चे खेल रहे थे, जिसमें पीड़ित बच्ची और आरोपी बच्चे शामिल थे। बताया जा रहा है कि बच्चे लुका-छिपी (छुपन-छुपाई) का खेल खेल रहे थे और इसी दौरान पास के ही एक खेत में जाकर छिप गए। खेत मालिक की नजर जब बच्चों पर पड़ी तो उसने मौके से बच्ची के माता-पिता को बुलाया और स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए।

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू आरोपियों की उम्र से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष द्वारा जिन पांच लोगों पर आरोप लगाया गया है, वे सभी खुद बच्चे हैं। नामजद बच्चों में से किसी की उम्र 7 वर्ष है, किसी की 10 वर्ष तो किसी की 12 वर्ष बताई जा रही है। उम्र और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बाल कल्याण और कानूनी मानकों के तहत परिजनों की मौजूदगी में बच्चों से पूछताछ कर रही है।

CO तिलहर विदुष सक्सेना का बयान: निष्पक्ष जांच जारी

पुलिस ने पीड़ित 9 वर्षीय बच्ची को तुरंत चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। विवेचना कर रहे सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं और साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अमहट मंडी में ऊंट के मुंह में जीरा वाली कार्रवाई!

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अमहट मंडी की समस्याएं सुलझने के बजाय अब आग में घी डालने का काम हो रहा है। व्यापारी जब मंडी अध्यक्ष मोहम्मद शमी उर्फ लईया के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने गए, तो उसी दिन 1 घंटे बाद अध्यक्ष को एक फर्जी नोटिस थमा दिया गया।

व्यापारियों का आरोप है कि मंडी अध्यक्ष 460977 रु का नोटिस भेजकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि अध्यक्ष का कहना है कि इस बिल का पैसा पहले ही जमा किया जा चुका है। मंडी अध्यक्ष ने कहा मंडी में अधिकतर व्यापारी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं और कमजोर दिल के हैं। अगर इसी तरह मंडी समिति के अधिकारी फर्जी नोटिस भेजेंगे तो किसी व्यापारी को हार्ट अटैक आ जाएगा। उसकी जिम्मेदारी मंडी समिति के अधिकारियों की होगी। उनका सीधा आरोप है कि यह नोटिस दबाव की राजनीति के तहत भेजी गई है ताकि व्यापारी मंडी की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत न कर सकें।

व्यापारियों का कहना है कि मंडी में अतिक्रमण, दबंग किराएदारी और सुरक्षा की समस्या जस की तस है। समाधान के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। शिकायत करने वालों को ही नोटिस भेजकर ष्आंखें दिखानेष का काम किया जा रहा है। मोहम्मद शमी उर्फ लईया ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना है कि प्रशासन इस ऊंट के मुंह में जीरा वाली कार्रवाई पर कब लगाम लगाता है, या फिर अमहट मंडी के व्यापारी ऐसे ही सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की स्थिति झेलते रहेंगे।

अयोध्या में एलटी छात्र के पास से मिली बम बनाने की पर्ची, जांच में जुटीं पुलिस व खुफिया एजेंसियां

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल प्रथम वर्ष के एक छात्र के पास बम बनाने से संबंधित जानकारी लिखी पर्ची मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली अयोध्या पुलिस मौके पर पहुंची और छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को भी जांच में लगाया गया है।

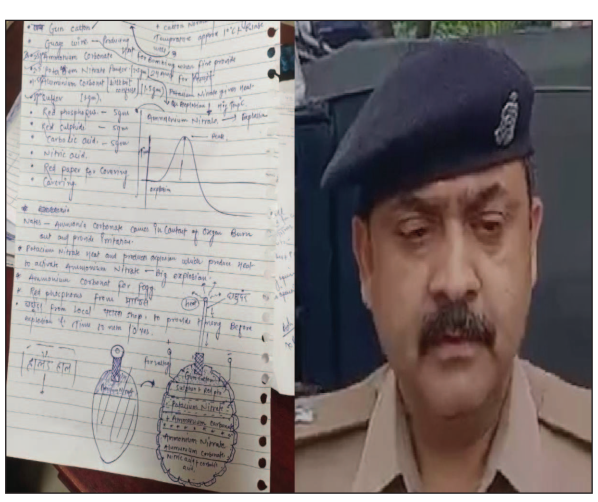

जानकारी के अनुसार, बलरामपुर निवासी मुस्लिम समुदाय का छात्र मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। शुक्रवार रात उसकी लैब में ड्यूटी थी। इसी दौरान उसके पास से एक पर्ची बरामद हुई, जिसमें कथित तौर पर बम बनाने की विधि, आकार और उसकी तीव्रता से संबंधित विवरण लिखा हुआ था। पर्ची मिलने की जानकारी पर कॉलेज प्रशासन सतर्क हो गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। साथ ही बरामद पर्ची की जांच की जा रही है कि उसका उद्देश्य क्या था और उसका किसी संदिग्ध गतिविधि से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जांच एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले में सभी तथ्यों की पुष्टि करने में जुटी है।

हलियापुर में हाईवे फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के हलियापुर कस्बे से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-330ए के दोनों ओर बने फुटपाथों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार सड़क सुरक्षा, सुचारु यातायात और पैदल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा।

बताया जा रहा है कि एनएचएआई की टीम पहले ही मौके पर पहुंचकर आंशिक कार्रवाई कर चुकी है तथा अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी जा चुकी है। अब नियमानुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकानदार स्वयं टीन शेड, छप्पर, सीढ़ियां, होर्डिंग अथवा अन्य अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं तो एनएचएआई, तहसील प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या कब्जा दंडनीय माना जाता है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है तथा आवश्यक होने पर एफआईआर जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार यदि एक बार कार्रवाई और चेतावनी के बाद भी दोबारा अतिक्रमण किया जाता है तो विशेष अभियान चलाकर बिना नए नोटिस के भी कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य हाईवे को अतिक्रमण मुक्त रखना और दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। मैनेजर रवि राय ने दूरभाष पर बताया कि हलियापुर कस्बे में फुटपाथों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द ही व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा।

आठ अगस्त को प्रयागराज आएंगे राहुल गांधी, पेपर लीक, शिक्षा घोटालों पर छात्रों से करेंगे सवाद

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। नीट और सीबीएसई घटनाक्रम को लेकर फिर देशभर कि राजनीति गर्म होने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17 जून को कोटा से छात्रों की गूंज अभियान का पहले चरण की शुरुआत करने के बाद दूसरा चरण 17 जुलाई को देहरादून में हुआ। इसके बाद तीसरा चरण प्रयागराज में 8 अगस्त को होना तय हो गया है। जबकि 9 अगस्त को दिल्ली में विशाल छात्र रैली के साथ इस चरण का समापन होना था। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा कार्यक्रम कि अनुमति नहीं मिलने से अब 'छात्र संवाद' 8 अगस्त को प्रयागराज सिविल लाइन्स स्थित केपी ग्राउंड में होना सुनिश्चित हो गया है।

पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद के बताया कि प्रयाग में आयोजित होने वाली 'छात्रों कि गूंज' कार्यक्रम में रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों के माहौल और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बताया कि राहुल के छात्र संवाद में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी सहित अन्य जिलों के छात्र शामिल होंगे।

कार्यक्रम कि तैयारी को लेकर रविवार को यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शहर जिला कमेटी के पदाधिकारी और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी के छात्र संवाद में प्रदेश भर के प्रतियोगी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर विवेकानंद पाठक ने बताया कि छात्र संवाद में हिस्सा लेने के लिये अब तक डेढ़ लाख से अधिक युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। शहर अध्यक्ष फुजैल हाशमी ने बताया कि 'छात्रों कि गूंज' कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौपी जा रही है।

सावन में हर शनिवार और सोमवार को स्कूलों में छुट्टी, यूपी के एटा जिले में नहीं खुलेंगे 12वीं तक के विद्यालय

आर्यावर्त संवाददाता

एटा। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए एटा में 12वीं तक के विद्यालयों को शनिवार और सोमवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सोरों और कछला घाट पर गंगाजल लेने पहुंचने वाले कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए जिले में शुक्रवार रात से रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है।

शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वहीं रोडवेज बसों का संचालन भी निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से कराया जाएगा। डायवर्जन व्यवस्था सोमवार की शाम छह बजे तक लागू रहेगी। यही व्यवस्था सात से 11 अगस्त, 14 से 17 अगस्त और 21 से 24 अगस्त तक प्रत्येक शुक्रवार से सोमवार शाम तक लागू रहेगी। डायवर्जन के दौरान अलीगढ़, पिलुआ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, बदायूं, बरेली, शिकोहाबाद और टूंडला की ओर से आने-जाने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इन्हें वैकल्पिक मार्गों से उनके गंतव्य की ओर निकाला जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान एटा-कासगंज मार्ग को वन-वे रखा जाएगा।

कई स्कूलों ने घोषित किया अवकाश

कांवड़ की भीड़भाड़ को देखते हुए शहर के कई प्रमुख स्कूलों ने अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय ट्रैफिक में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किया गया है। भीड़ की आशंका को देखते हुए शनिवार और सोमवार को स्कूल बंद रखने का निर्णय स्कूल प्रबंधन द्वारा लिया गया है।

यहां से होगा वाहनों का संचालन

- अलीगढ़ व पिलुआ से मैनपुरी जाने वाले भारी वाहन एटा बाईपास से डायवर्ट किए जाएंगे।

- अलीगढ़ व पिलुआ से फिरोजाबाद जाने वाले वाहन मलावन, कुरावली, घिरोर और शिकोहाबाद होकर जाएंगे।

- एटा से बदायूं व बरेली जाने वाले भारी वाहन ओन घाट चौकी, सिढ़पुरा, गंजडुंडवारा और कादरगंज मार्ग से भेजे जाएंगे।

- मैनपुरी से आने वाले भारी वाहनों को एटा बाईपास से अलीगढ़ भेजा जाएगा।

- कासगंज से फिरोजाबाद जाने वाले वाहन सौरभ ढाबा से अमांपुर, एटा बाईपास, मलावन, कुरावली, घिरोर और शिकोहाबाद होकर गुजरेंगे।

- शिकोहाबाद से एटा आने वाले सभी भारी, हल्के एवं आवश्यक वस्तुओं के वाहन घिरोर-मैनपुरी मार्ग से संचालित होंगे।

- टूंडला से आने वाले वाहन फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, घिरोर, कुरावली, मलावन, एटा बाईपास, सिढ़पुरा और गंजडुंडवारा होकर बदायूं-बरेली जाएंगे।

- एटा-कासगंज मार्ग वन-वे रहेगा।

आकर्षण का केन्द्र रहा दुनिया का सबसे ऊंचा अलम

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अंजुमन असगरिया गोराबारिक अमहट सुल्तानपुर की तरफ से वृहस्पतिवार को हुसैनिया नौतामीर गोराबारिक अमहट में रात 8सजे एक मजलिस का आयोजन किया गया इसके पहले पेश ख्वानी आबिस सुल्तानपुरी आरिफ सुल्तानपुरी सलीम बलरामपुरी व मारूफ सिरसवी ने की और मजलिस मौलाना डाक्टर अबूजर अली बिहार ने पढ़ी। उन्होंने ने कहा आज की रात कर्बला के सबसे नन्हे शहीद हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद मनायी गई। जिसकी उम्र 6माह थी जिसे तीन दिन का भूखा प्यासा कर्बला में गले पर तीर मारकर शहीद कर दिया गया मजलिस के बाद शबीह गहवारा झूला हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम निकाला गया और रात भर शब्बेदारी हुई जिसमें मुकाती

अंजुमनों के अलावा बाहरी अंजुमन अंजुमन गुन्चये मजलूमिया फैजाबाद अंजुमन जवानाने हुसैनी आजमगढ़ ने नौहा मातम किया संचालन अनीस जायसी की । शब्बे दारी के बाद सुबह 5बजे 18बनी हाशिम के शबीह ताबूत का जुलूस हुसैनिया नौतामीर गोराबारिक से उठकर हुसैनिया शेखानी पर समाप्त हुआ दौराने जुलूस मौलाना सैयद शारिब अब्बास अकबरपुर मौलाना सैयद नजर मोहम्मद जैनबी दिल्ली ने तकरीर की जुलूस में आकर्षक का केन्द्र रहा। 110फिट ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा अलम जिसकी जियारत के लिए दूर दराज से भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया याद रहे यह अलम अमन और शांति का प्रतीक और सुल्तानपुर जनपद की शान है सबसे पहले यह अलम हुसैन ने अपने सेनापति हजरत अब्बास के हाथों से कर्बला में बुलन्द करके अमन और शांति की अपील की थी आज हम लोग भी यह अलम बुलन्द करके दुनिया से अमन शान्ति की अपील करते हैं।इसकी जानकारी हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर ने दी है।

लखनऊ में विकास कार्यों की रफ्तार पर नगर आयुक्त की पैनी नजर

झील, नाला, कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी और जोनल कार्यालय सहित कई परियोजनाओं का किया निरीक्षण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी में विकास परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत योजना के तहत विकसित की जा रही हैवतमऊ झील, सीएम ग्रिड परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन नाला, कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, इंटर कॉलेज के नए कक्षों तथा जोनल कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।नगर आयुक्त के साथ अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (सिविल) महेश वर्मा, संबंधित अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रत्येक परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और जनता को समय पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।निरीक्षण की शुरुआत नगर आयुक्त ने जोन-8 में अमृत योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही हैवतमऊ झील से की। अधिकारियों ने बताया कि झील के विकास का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और केवल कुछ छोटे कार्य शेष हैं। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कर झील को नागरिकों के उपयोग के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं शहर के पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।इसके बाद नगर आयुक्त ने सीएम ग्रिड योजना के तहत रजनी खंड में निर्माणाधीन नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर नाला निर्माण पूरा होने से क्षेत्र में जलभराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।निरीक्षण के क्रम में नगर आयुक्त सेक्टर-जी स्थित कथा पार्क पहुंचे, जहां निर्माणाधीन कम्युनिटी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भवन निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और शेष कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएं, ताकि स्थानीय नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक भवन उपलब्ध हो सके।नगर आयुक्त ने जोन-8 में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा पूरे शहर में 40 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इसलिए इनके निर्माण में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।इसके बाद उन्होंने कश्मीरी मोहल्ला इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर वहां निर्माणाधीन नए क्लासरूम और अन्य विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

जिली बिल की समस्याओं के समाधान के लिए पूरे प्रदेश में अगस्त भर लगेंगे विशेष शिविर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने बिजली उपभोक्ताओं की बिल संबंधी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रदेश में एक माह का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रबंध निदेशक नितीश कुमार के निर्देश पर 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक सभी विद्युत वितरण निगमों और केस्को कानपुर के खंडीय, उपखंडीय, सहायक अभियंता (वितरण एवं वाणिज्य) तथा अधिशासी अभियंता कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों तथा केस्को कानपुर को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों का मौके पर समाधान करना और उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना है।यूपीपीसीएल ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक शिविर में बिल संशोधन, नए बिजली कनेक्शन, विद्युत भार वृद्धि, खराब मीटर बदलने, श्रेणी परिवर्तन, बिल जमा करने तथा बिजली आपूर्ति से संबंधित अन्य शिकायतों का भी निस्तारण किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उपभोक्ता को शिकायत दर्ज किए बिना वापस नहीं भेजा जाएगा।शिविरों में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का पंजीकरण 1912 हेल्पडेस्क पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक शिविर स्थल पर पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर और लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। शिकायतों के समाधान के बाद उन्हें 1912 पोर्टल पर बंद करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में बैंकिंग बाधाओं पर यूपी सोलर एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन का खुला पत्र

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रधानमंत्री सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आ रही बैंकिंग संबंधी बाधाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन (यूपीएसईडीए) ने प्रधानमंत्री कार्यालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा योजना की नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड को खुला पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से सोलर ऋण स्वीकृति के लिए मकान की रजिस्ट्री या म्यूटेशन को अनिवार्य किए जाने से योजना की रफ्तार बुरी तरह प्रभावित हो रही है और एक करोड़ घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य संकट में पड़ सकता है।एसोसिएशन के सचिव एवं संस्थापक संचित राज गर्ग की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी, जिला प्रशासन, परियोजना अधिकारी, कार्यदायी संस्थाएं तथा सोलर वेंडर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद बैंकों की नई शर्तों ने योजना के क्रियान्वयन में गंभीर व्यावहारिक समस्याएं खड़ी कर दी हैं।पत्र में बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों तक जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से दो लाख रुपये तक का सोलर ऋण बेहद सरल प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराया जाता था। इसके लिए केवल घरेलू बिजली बिल, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे तीन दस्तावेज पर्याप्त होते थे। ऋण स्वीकृत होने के बाद सोलर संयंत्र शीघ्र स्थापित कर दिए जाते थे और लगभग दस दिनों के भीतर केंद्र सरकार की 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी सीधे ऋण खाते में जमा हो जाती थी। इसी सरल व्यवस्था के कारण देशभर में लगभग 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा सके।एसोसिएशन का आरोप है कि 1 जून 2026 के बाद जन समर्थ पोर्टल पर बैंकों ने मकान की रजिस्ट्री अथवा दाखिल-खारिज का दस्तावेज अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के ऋण आवेदन निरस्त हो रहे हैं। संगठन का कहना है कि देश के अधिकांश परिवार पैतृक या संयुक्त पारिवारिक मकानों में रहते हैं, जहां बिजली का कनेक्शन तो उपभोक्ता के नाम पर होता है, लेकिन संपत्ति माता-पिता, पति, भाई या अन्य परिजनों के नाम दर्ज होती है। ऐसी स्थिति में बैंक ऋण देने से इनकार कर रहे हैं।खुले पत्र में कहा गया है कि इस नई व्यवस्था के कारण योजना की गति लगभग थम गई है और यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो सरकार का एक करोड़ घरों तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।

लखनऊ पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार किए बरामद

लखनऊ। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले का लखनऊ पुलिस ने खुलासा करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप, सरिया और लकड़ी के डंडे भी बरामद किए हैं। मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।पुलिस के अनुसार पुलिस आयुक्त तरुण गाबा तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) मो. मुश्ताक, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार और सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में थाना गोसाईगंज पुलिस एवं दक्षिणी जोन की सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया।

आशियाना पुलिस ने दो शातिर चोर दबोचे, चोरी के जेवर और बिजली के तार बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। आशियाना पुलिस ने चोरी की दो अलग-अलग घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात और विद्युत तार बरामद किए हैं। बरामदगी के आधार पर दोनों मुकदमों में अतिरिक्त धाराएं बढ़ाते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार 13 जुलाई 2026 को एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड निवासी किरन श्रीवास्तव ने अपने निर्माणाधीन मकान से बिजली के तार चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद 17 जुलाई 2026 को रश्मिखंड, शारदानगर निवासी मंगल प्रसाद शर्मा ने घर का ताला तोड़कर चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों मामलों की विवेचना अलग-अलग पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही थी।

घटनाओं के खुलासे के लिए आशियाना पुलिस लगातार सुरागरसी कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने देवीखेड़ा से इको गार्डेन जाने वाली सड़क पर घेराबंदी कर दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उनकी पहचान राहिल उर्फ लंगड़ा (44) और मो. इस्माइल उर्फ टिल्लू (42), निवासी कांशीराम कॉलोनी, सालेहनगर, थाना आशियाना के रूप में हुई।तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के एक जोड़ी पाजेब, एक जोड़ी पायल, पांच पायल, एक ब्रेसलेट, एक कमरबंद, एक सफेद धातु की चेन, एक पीली धातु की अंगूठी तथा चोरी किए गए विद्युत तार बरामद किए। बरामद सामान की पहचान दोनों मुकदमों से संबंधित चोरी की संपत्ति के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों मामलों में बरामदगी की धारा भी जोड़ दी।जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी राहिल उर्फ लंगड़ा एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध लखनऊ के आशियाना, मड़ियांव, कैन्ट, चिनहट, पीजीआई, हुसैनगंज और कृष्णानगर सहित गोरखपुर के तिवारीपुर थाने में चोरी और चोरी का माल रखने जैसे गंभीर मामलों के 18 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी मो. इस्माइल उर्फ टिल्लू के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थानों से जुटाई जा रही है।इस कार्रवाई को आशियाना थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि चोरी की घटनाओं में शामिल अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में चार पहिया वाहनों पर पुलिस का सख्त शिकंजा, छह दिन के अभियान में 1359 चालान और 41 वाहन सीज

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लखनऊ पुलिस ने चार पहिया वाहनों के विरुद्ध छह दिवसीय विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया। 26 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन रात 9:30 बजे से 12:00 बजे तक संचालित इस अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 1359 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 41 वाहनों को सीज किया गया।पुलिस आयुक्त के निर्देशन तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) के पर्यवेक्षण में कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों, क्रिटिकल कॉरिडोर प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और बीट इंचार्जों ने बैरियर लगाकर पुलिस बल के साथ विशेष जांच अभियान चलाया। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और नागरिकों को नियमों के प्रति जागरूक करना था।अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों, हूटर का अवैध प्रयोग करने, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने, अमान्य दस्तावेज रखने, तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। कई वाहनों को आवश्यक दस्तावेज न होने, बिना नंबर प्लेट पाए जाने अथवा वाहनों में अवैध बदलाव किए जाने के कारण सीज भी किया गया। यह अभियान शहर के सभी पांच पुलिस जोनों—पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी—में एक साथ चलाया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर विशेष जोर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा नवजात शिशुओं के समुचित पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। ऐशबाग स्थित रेलवे पॉलीक्लिनिक में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस सप्ताह के दौरान महिलाओं, गर्भवती माताओं और महिला कर्मचारियों को स्तनपान के महत्व, सही तकनीक और पोषण संबंधी आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी।यह कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बादशाहनगर रमेश चंद्र के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण की रोकथाम

और माताओं में स्तनपान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम ₹जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपानः जो कारगर है उसे मजबूत करें₹ रखी गई है। यह थीम नवजात शिशुओं के लिए स्तनपान को सबसे सुरक्षित, प्राकृतिक और प्रभावी पोषण का माध्यम मानते हुए समाज में इसके प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है।कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बताया गया कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को मां का पहला गाढ़ा पीला दूध (कोलोस्ट्रम) अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि यह नवजात की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही जीवन के पहले छह माह तक केवल मां का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक विकास को मजबूती मिलती है।इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय तिवारी ने रेलवे पॉलीक्लिनिक में उपस्थित महिला रोगियों एवं महिला कर्मचारियों को संबोधित करते हुए स्तनपान के स्वास्थ्य संबंधी लाभों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित स्तनपान न केवल शिशु को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, बल्कि माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने महिलाओं से शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार इसे नियमित रूप से जारी रखने का आग्रह किया।सप्ताह भर चलने वाले इस जागरूकता अभियान के दौरान रेलवे चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को स्तनपान की सही विधि, मातृ पोषण, नवजात शिशु की देखभाल और भ्रांतियों से बचने संबंधी जानकारी भी दी जाएगी।

लखनऊ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा, दो शातिर चोर गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए जहां 1359 वाहनों के चालान किए और 41 वाहन सीज किए, वहीं आशियाना पुलिस ने चोरी की दो वारदातों का सफल खुलासा कर दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा निगोहां पुलिस ने घरेलू विवाद के बाद घर छोड़कर चले गए एक युवक को महज 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया।पुलिस आयुक्त के निर्देशन में 26 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन रात्रि 9:30 बजे से 12:00 बजे तक चार पहिया वाहनों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने, हूटर और ब्लैक फिल्म का अवैध प्रयोग करने, बिना नंबर प्लेट, अमान्य दस्तावेज रखने, तेज रफ्तार से वाहन चलाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। छह दिन तक चले इस अभियान में कुल 1359 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 41 वाहनों को सीज किया गया। कई वाहन वैध दस्तावेज न होने और उनमें अवैध परिवर्तन पाए जाने के कारण जब्त किए गए।यह अभियान शहर के सभी पांच पुलिस जोनों में एक साथ चलाया गया। कैसरबाग, हुसैनगंज, नखास, अटल चौक, तेलीबाग चौराहा, 1090 चौराहा, आईटी चौराहा, निशातगंज क्रासिंग, अवध चौराहा सहित प्रमुख बाजारों और व्यस्त स्थानों पर पुलिस टीमों ने बैरियर लगाकर वाहनों की सघन जांच की। कार्रवाई के साथ-साथ वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के प्रति भी जागरूक किया गया। पुलिस ने नागरिकों से शराब पीकर वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, ब्लैक फिल्म और हूटर का इस्तेमाल न करने तथा उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट का उपयोग करने की अपील की है।उधर, आशियाना थाना पुलिस ने जुलाई माह में हुई चोरी की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवीखेड़ा से इको गार्डेन जाने वाली सड़क से राहिल उर्फ लंगड़ा और मो. इस्माइल उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से चोरी के जेवरात और विद्युत तार बरामद किए गए, जिनमें एक जोड़ी पाजेब, एक जोड़ी पायल, पांच पायल, एक ब्रेसलेट, एक कमरबंद, एक सफेद धातु की चेन, एक पीली धातु की अंगूठी तथा बिजली के तार शामिल हैं। बरामदगी के आधार पर दोनों मुकदमों में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

पप्पू यादव के बयान के विरोध में विश्व हिन्दू रक्षा परिषद का प्रदर्शन, पुतला फूंककर सार्वजनिक माफी की मांग

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पप्पू यादव के कथित सनातन धर्म संबंधी बयान के विरोध में विश्व हिन्दू रक्षा परिषद (वीएचआरपी) ने शनिवार को गोमती नगर स्थित विशाल खंड-2 कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने बयान को सनातन धर्म, संत समाज और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की।प्रदर्शन के दौरान विश्व हिन्दू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि सनातन धर्म, साधु-संतों और धार्मिक परंपराओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव द्वारा संत समाज और भगवा वस्त्र की गरिमा पर की गई

टिप्पणी करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है।उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के आचरण के आधार पर पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना अनुचित और निंदनीय है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपरा में संत समाज का महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनकी गरिमा पर प्रश्नचिह्न लगाना समाज की आस्था पर चोट पहुंचाने जैसा है।गोपाल राय ने यह भी आरोप लगाया कि पप्पू यादव द्वारा पहने गए कुर्ते पर राम मंदिर का चित्र अंकित था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और लंबे संघर्ष का प्रतीक है तथा उसकी गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद सहित किसी भी मंच पर श्रीराम मंदिर जैसे धार्मिक विषयों को लेकर दिए जाने वाले बयान केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं होते, बल्कि वे करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं।उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दू रक्षा परिषद लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर सनातन धर्म और धार्मिक आस्थाओं के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की कि पप्पू यादव अपने बयान पर देशभर के सनातन धर्मावलंबियों और संत समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और धार्मिक आस्थाओं के सम्मान की रक्षा का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में मनीष राय, हिमांशु धवल, दिलीप सिंह, पंकज अग्रवाल, ओम शंकर गुप्ता, अनिल यादव, ममता चौधरी, उमा शंकर, शिवम कश्यप, कार्तिका माथुर, शुभम श्रीवास्तव, कौशल किशोर द्विवेदी, भव्य श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सैरपुर पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा, लाखों के जेवर बरामद, चोरी में प्रयुक्त अपाचे बाइक भी जब्त

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। सैरपुर थाना पुलिस और दक्षिणी जोन की सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बंद मकानों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के बड़ी मात्रा में आभूषण तथा वारदात में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी में चोरी, गैंगस्टर, शस्त्र अधिनियम और मादक पदार्थ अधिनियम सहित दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस के अनुसार 26 जुलाई 2026 को न्याय विहार, सीतापुर रोड निवासी आशीष कुमार ने सैरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 जुलाई को दोपहर के समय उनके बंद मकान का ताला तोड़कर करीब 2.50 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई।जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपी अपाचे मोटरसाइकिल से किसी नई वारदात को अंजाम देने के इरादे से रैथा अंडरपास की ओर से छठामील की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर सैरपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने तरहिया मोड़, कमलाबाद बढ़ौली के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।प ूछताछ में आरोपी ने अपना नाम फैसल उर्फ छोटू पुत्र अलीम खान, निवासी गऊघाट, थाना ठाकुरगंज, मूल निवासी तंबौर, जनपद सीतापुर बताया। वह पेशे से वाहन मैकेनिक है।

पेपर लीक बहस के दौरान विपक्षी दलों ने खोया सुनहरा अवसर

केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार होने वाली पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ध्वनिमत से करा लिया। इस विधेयक पर बहस के दौरान यह बात स्पष्ट हो गई कि विरोधी दल छात्र हितैषी बनने का केवल दिखावा कर रहे थे। उनका वास्तविक उद्देश्य छात्रों के नाम पर संसदीय कामकाज को लटकाना, भटकाना व अटकाना ही था। कांग्रेस सहित विरोधी दलों के सांसदों ने पेपरलीक के मुद्दे पर केवल हंगामा और ओछी व गलत बयानबाजी ही करी। लोकसभा की बहस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष द्वारा छात्र आंदोलन की आड़ में देश को अराजकता की आग में झोंक कर उसमें अपनी राजनीतिक रोटिया सेंकने के सपने को चूर चूर कर दिया है। बहस के दौरान राजग गठबंधन के सांसदों ने स्पष्ट कर दिया कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम एनडीए सरकार में ही होगा जबकि विरोधी दल पूरी तरह से दिशाहीन और विभाजित दिखाई दिए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष को तथ्यों, तर्कों व आंकड़ों से बेअसर व हताश कर दिया। अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन के पटल पर गलत आंकडे.रखे। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फ़ोर्स में शामिल डॉ वी. कामकोटि को गौ-मूत्र विशेषज्ञ कहकर उनका उपहास उड़ाया। वी. कामकोटि के 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। प्रियंका गाँधी को इस बात का न केवल संसद वरन सोशल मीडिया पर भी करारा जवाब मिला। कांग्रेस को इस बात का भी दर्द हो रहा होगा कि आधार के डिजाइनर नंदन नीलेकणि जो कभी कांग्रेस के साथ थे और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़े थे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हैं।

कांग्रेस की बहस में रही सही धार राहुल गांधी ने संसद में इडियट और अंधभक्त भक्त जैसे अमर्यादित शब्दों का उपयोग करके कुंद कर दी और बता दिया कि अब यह मुद्दा उनके हाथ से जा चुका है। उन्होंने दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर गोली चलने का झूठा दावा किया और गृहमंत्री अमित शाह पर हमलावर हो गए। उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि छात्र आंदोलन के दौरान गृह मंत्री विदेश चले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गृहमंत्री के काफिले में तीस गाड़ियाँ हैं। राहुल गांधी का पूरा बयान हताशा और निराशा से भरा हुआ और झूठ का पुलिंदा मात्र था। राहुल गाँधी हमेशा की तरह बहस के बजाए नौटंकी करते दिखे। खुले माइक पर माइक बंद होने का आरोप लगाया। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मुद्दा ही बदल दिया और चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाने लगे। सपा मुखिया ने कहा कि जो लोग मंदिरों मे चढावा चोरी नहीं रोक सकते वह पेपर लीक क्या रोक पाएंगे। बहस के दौरान इंडी गठबंधन के सभी सांसद कुंठित नजर आ रहे थे। एनडीए सांसदों ने पूरी तैयारी के साथ बहस में भाग लेकर विरोधियो व उनकी रणनीति को बेनकाब किया। विधेयक प्रस्तुत करते समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2014 के पूर्व पेपर लीक जैसी तमाम घटनाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा और फिर बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या से लेकर अनुराग ठाकुर तक ने अपने तथ्यों से विपक्ष की पोल खोल दी। सदन में सरकार की ओर से बताया गया कि परीक्षा को लेकर देश प्रदेशों में तरह-तरह की घटनाएं होती रही हैं जिनमें पेपर लीक भी है। यह एक प्रदेश या एक सरकार तक सीमित नहीं है। 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा, बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा, 2011 में आल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, 2012 में एम्स दिल्ली का पेपर लीक, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक, 2023 में महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाएं घटीं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2014 के पूर्व यूपीए-2 के शासनकाल में 22 बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार, बंगाल में टीएमसी, यूपी में सपा के शासनकाल में तो नकल माफिया का महामंत्र ही विकसित हो गया था। अब बिल लोकसभा से पास हो चुका है, इंडी गठबंधन के नेताओं को जो कहना है जो आरोप लगाना है लगाते रहें अन्ततः नया कानून ही सच्चाई होगी। छात्रों के नाम पर बनी सीजेपी भी बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 2000 से अधिक अपराधियों की जंतर मंतर पर उपस्थिति चिह्नित की है । छात्रों को ध्यान रखना होगा कि 1973 से लेकर 1984 तक विभिन्न छात्र आंदोलनों के दौरान कम से कम 800 छात्रों की पुलिस की गोली व लाठी से मौत हुई थी तब देश में कांग्रेस की सरकारें ही थी। गांधी परिवार परिवार छात्र आंदोलन की आड़ में केवल अपनी वंशवादी राजनीति को धार देने और देश की जनता को भ्रमित व अराजकता की आग में झोकने का काम कर रहा है।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों पर मोदी सरकार के तर्कपूर्ण जवाब

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का जोरदार प्रतिवाद किया। उन्होंने अदालत से कहा कि बहस की शुरुआत इस धारणा से नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण करेंगे।

नीरज कुमार दुबे

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ऐसी बहस छिड़ी, मानो लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं में से एक का भविष्य न्यायालय के कटघरे में खड़ा हो। एक ओर संविधान की आत्मा और निष्पक्ष चुनाव की कसौटी पर सवाल उठाते न्यायाधीश थे तो दूसरी ओर संसद की सर्वोच्चता और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पक्ष मजबूती से रखती केंद्र सरकार। सवालों और जवाबों का यह सिलसिला कई बार अदालत की बहस से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं पर गहन विमर्श में बदल गया।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले यही सवाल उछाला कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) का पद लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर उनके चयन की प्रक्रिया ऐसी क्यों न हो, जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह न रहे? अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र होकर काम करे, इतना पर्याप्त नहीं है; उसे स्वतंत्र दिखाई भी देना चाहिए।

इसी संदर्भ में अदालत ने सरकार से सीधा प्रश्न किया कि संसद ने 2023 का कानून बनाते समय चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर रखने का निर्णय आखिर किस आधार पर लिया? पीठ ने याद दिलाया कि सीबीआई निदेशक और लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों के चयन में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका स्वीकार की गई है, फिर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के मामले में यह व्यवस्था क्यों बदली गई?

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तर्क का जोरदार प्रतिवाद किया। उन्होंने अदालत से कहा कि बहस की शुरुआत इस धारणा से नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत आचरण करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा और पवित्रता है तथा जनता को उनके निर्णयों पर विश्वास होना चाहिए। तुषार मेहता ने सवालिया अंदाज में कहा, 'यदि प्रधानमंत्री के फैसलों पर भरोसा ही नहीं किया जाएगा, तो क्या फिर मंत्रिमंडल के गठन के समय भी किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से सलाह लेना अनिवार्य कर दिया जाए?'

उन्होंने यह भी दलील दी कि केवल इसलिए कि कार्यपालिका के पास संख्यात्मक बहुमत है, यह मान लेना उचित नहीं कि वह संविधान विरोधी या दुर्भावनापूर्ण निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के तीनों अंग यानि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और एक संस्था दूसरी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

लेकिन अदालत ने तुरंत स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री पर अविश्वास जताना नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया का है जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा, ₹हम यह नहीं कह रहे कि वर्तमान समिति ने निष्पक्षता नहीं बरती है। लेकिन जैसे न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए, उसी प्रकार चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में भी निष्पक्षता दिखाई देनी चाहिए।'

इसी दौरान अदालत ने सरकार से एक और तीखा सवाल पूछा। पीठ ने याद दिलाया कि पहले भी अदालत ने निर्वाचित सरकार पर भरोसा जताते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री न बनाने की अपेक्षा की थी। ऐसे में आज सरकार में कितने मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं? इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी तय होती है। हम आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 2023 के उस कानून को लेकर है, जिसके तहत राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री वाली चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं। इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। बाद में संसद ने कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी अदालत से कहा कि संसद की विधायी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाना न्यायिक मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। उनका कहना था कि केवल इसलिए कि कोई दूसरा मॉडल बेहतर हो सकता है, संसद द्वारा चुनी गई व्यवस्था को असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'संसद को इस प्रकार बाधित नहीं किया जा सकता।'

सरकार ने अपने हलफनामे में भी यही रुख दोहराया। केंद्र ने कहा कि यह आशंका पूरी तरह काल्पनिक है कि चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होने से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता स्वतः प्रभावित हो जाएगी। सरकार ने याद दिलाया कि सात दशक से अधिक समय तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह कार्यपालिका द्वारा होती रही, लेकिन इस दौरान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी बाधित नहीं हुए। इसलिए केवल आशंकाओं के आधार पर कानून को दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता।

सुनवाई के दौरान केंद्र ने यह आग्रह भी किया कि मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं, इसलिए इसे बड़ी संविधान पीठ को भेजा जाए। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता डी. शेषाद्रि नायडू, गोपाल शंकरनारायणन, प्रशांत भूषण और संजय पारिख ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि लगभग 20 दिन तक विस्तृत सुनवाई चलने के बाद अब इस आधार पर मामला बड़ी पीठ को भेजने की मांग करना केवल सुनवाई को टालने का प्रयास है।

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की गई है। अब निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह निर्णय केवल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, संसद की विधायी शक्ति और जनता के भरोसे के बीच संतुलन की नई संवैधानिक रेखा भी खींच सकता है।

व्यंग्य

आय में सुस्ती

आम जन का जीवन स्तर गतिरुद्ध हो, शिक्षा उज्ज्वल भविष्य की सीढ़ी नज़र ना आ रही हो, और बेरोजगारी से निपटने के उपाय दिखावटी बन गए हों, तो कैसी सामाजिक शांति की आशा की जा सकती है?

विभिन्न जन समूहों में असंतोष क्यों फैल रहा है, सरकार चाहे तो इसे खुद अपने आंकड़ों से समझ सकती है। खुद उसकी नीतियों ने युवा वर्ग में भविष्य के प्रति निराशा भरी है, तो बहुसंख्यक ग्रामीण आबादी की जिंदगी को दूभर बनाया है। कुछ बानगियों पर गौर कीजिए। 2024 में युवा बेरोजगारी दूर करने के लिए धूम-धड़ाके से शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अपने लक्ष्य से 99 प्रतिशत पीछे चल रही है। कॉरपोरेट मंत्रालय ने एक आरटीआई अर्जी पर बताया कि 30 अप्रैल 2026 तक कंपनियों ने 2.97 लाख इंटर्नशिप अवसर पैदा किए, जो दो साल के लक्ष्य का लगभग दसवां हिस्सा है। तस्वीर और निराशाजनक हो जाती है, जब ध्यान जाता है कि वास्तविक ऑफर 1.73 लाख ही रह गए।

इनमें से जिन लोगों को ऑफ़र दिए गए, उनमें से लगभग 18,000 लोग ही काम पर पहुंचे। उनमें से केवल 5,200 लोग अंत तक टिके पाए। इस बीच ये आंकड़ा भी चर्चित हुआ है कि केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए आवंटन 2013-14 (4.6 फीसदी) की तुलना में 2025-26 में आधा (2.5 प्रतिशत) रह गया है। इसी बीच राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक ताजा रिपोर्ट से सामने आया है कि सिर्फ 27.7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय में पिछले वर्ष वृद्धि दर्ज हुई। यह सितंबर 2024 से शुरू हुए इस सर्वे का सबसे निचला स्तर है। इसके मुताबिक 52.6 फीसदी परिवारों की आय में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि 19.8 प्रतिशत परिवारों की आय गिरी।

यानी 72 फीसदी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार दर्ज नहीं हुआ। आय में सुस्ती और वित्तीय दबाव के कारण अनौपचारिक माध्यमों (जैसे रिश्तेदारों, दोस्तों, या स्थानीय साहूकारों) से कर्ज लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे परिवारों की संख्या 23.6 प्रतिशत हो गई है। जब इस तरह लोगों का जीवन स्तर गतिरुद्ध हो, जमीनी स्तर पर अपनी जर्जर स्थिति के कारण शिक्षा उज्ज्वल भविष्य की सीढ़ी अब नज़र ना आ रही हो, और विकराल बेरोजगारी से निपटने के उपाय दिखावटी बन कर रह जाएं, तो समाज में कैसी स्थिरता और शांति की आशा की जा सकती है?

ब्लॉग

अभिजीत दीपके, सौरव दास, रिचा चड्ढा अनजाने में मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं या फिर जानबूझकर बदतमीजी कर रहे हैं?

नीरज कुमार दुबे

लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है और सत्ता की आलोचना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत मानी जाती है। लेकिन जब विरोध की भाषा शालीनता की सीमा लांघकर व्यक्तिगत अपमान में बदल जाए, जब तर्क और तथ्यों की जगह गाली-गलौज और कटाक्ष ले लें, और जब वरिष्ठों के सम्मान जैसी बुनियादी सामाजिक मर्यादाओं का भी मजाक उड़ाया जाने लगे, तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह लोकतांत्रिक विरोध है या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में सभ्य संवाद की संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश है?

हाल के दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके, उसके प्रवक्ता सौरव दास और अभिनेत्री रिचा चड्ढा के बयानों ने इसी बहस को जन्म दिया है। तीनों के बयान अलग-अलग संदर्भों में आए, लेकिन उनकी भाषा और दृष्टिकोण में जो समानता दिखाई देती है वह है व्यक्तिगत कटाक्ष, वरिष्ठों के प्रति असम्मान और मर्यादा की सीमाओं को लांघने की प्रवृत्ति।

अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के लिए जारी वीडियो संदेश पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि ₹आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है।₹ यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय बनाने और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए पारित कानून को विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। देखा जाये तो कोई भी व्यक्ति सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है, कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठा सकता है या सरकार से जवाब मांग सकता है। लेकिन किसी के व्यक्तित्व या शारीरिक स्वरूप पर टिप्पणी करना क्या स्वस्थ लोकतांत्रिक आलोचना कहलाएगी? क्या इससे छात्रों की समस्या का कोई समाधान निकलता है? यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी होने के बाद क्या दिपके और उनके सहयोगी इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि अब देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए भी घटिया और व्यक्तिगत भाषा का इस्तेमाल सामान्य मानने लगे हैं? जिस नेता को दुनिया में सबसे अधिक वोट प्राप्त कर लोकतांत्रिक जनादेश मिला हो, उसके साथ असहमति पूरी तरह स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन क्या उसका अपमान लोकतांत्रिक अधिकार की श्रेणी में रखा जा सकता है? सौरव दास का बयान इस बहस को और गंभीर बना देता है। जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ इस्तेमाल हुई अपमानजनक भाषा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता और लोकतंत्र में ₹जोकर₹ को स्वीकार करना चाहिए। देखा जाये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन किसी दिवंगत व्यक्ति या किसी के परिवार के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों का समर्थन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सार्वजनिक संवाद के स्तर को गिराना माना जायेगा। लोकतंत्र में तीखी आलोचना की पूरी गुंजाइश है, लेकिन व्यक्तिगत अपमान और विशेषकर दिवंगत परिजनों को निशाना बनाना स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं माना जाता।

भारत के मतदाताओं ने बार-बार यह संकेत दिया है कि वे नीतियों पर बहस चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अभद्रता को पसंद नहीं करते। राजनीतिक इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां तीखी व्यक्तिगत टिप्पणियों की तुलना में मुद्दों पर आधारित राजनीति को अधिक स्वीकार्यता मिली। ऐसे में यह मान लेना कि अपमानजनक भाषा ही जनभावना का प्रतिनिधित्व करती है, वास्तविकता से दूर आकलन है।

दूसरी ओर, अभिनेत्री रिचा चड्ढा का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी मानसिकता की झलक देता है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा कि केवल उम्र के आधार पर सम्मान नहीं मिलना चाहिए और अपनी बात को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों और उपमाओं का प्रयोग किया जोकि अपमानजनक और असंवेदनशील थीं। किसी व्यक्ति का सम्मान केवल उम्र से नहीं, उसके आचरण से भी जुड़ा हो सकता है, यह तर्क अपनी जगह है। लेकिन क्या इस विचार को व्यक्त करने के लिए पूरे वरिष्ठ वर्ग का उपहास उड़ाना, उनकी शारीरिक स्थिति पर कटाक्ष करना और उन्हें अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग करना उचित माना जा सकता है? रिचा चड्ढा को यह पता होना चाहिए कि भारतीय समाज में बुजुर्गों का सम्मान केवल परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन का महत्वपूर्ण आधार रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि रिचा चड्ढा इससे पहले भी कई विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। ऐसे में यह धारणा भी मजबूत होती है कि फिल्म और मनोरंजन जगत के कुछ कलाकार अपनी नई फिल्म या वेब सीरीज के रिलीज़ से पहले चर्चा में बने रहने और लाइमलाइट हासिल करने के लिए जानबूझकर विवादित बयान देते हैं।

देखा जाये तो सरकारों से सवाल पूछना आवश्यक है, आंदोलनों का होना भी लोकतंत्र का हिस्सा है और सार्वजनिक हस्तियों की आलोचना भी पूरी तरह वैध है। लेकिन यदि आलोचना की भाषा ही अपमान में बदल जाए, यदि असहमति की जगह व्यक्ति और उसके परिवार को निशाना बनाया जाए और यदि वरिष्ठों के प्रति सम्मान को ही पिछड़ापन बताने की कोशिश होने लगे, तो यह केवल राजनीतिक या वैचारिक बहस नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक संस्कारों के क्षरण का संकेत बन जाती है।

आखिरकार लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं चलता, बल्कि जिम्मेदारियों से भी चलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण संवाद की मर्यादा भी है। असहमति का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन अभद्रता और व्यक्तिगत अपमान किसी भी लोकतांत्रिक समाज को मजबूत नहीं, बल्कि कमजोर ही करते हैं।

राम मंदिर: दर्शन पास व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब ट्रस्ट के 3 सीए को भी मिला ये अधिकार

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था को और भी पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के मकसद से एक अहम बदलाव किया है। जिसके तहत दर्शन पास जारी करने की सुविधा अब ट्रस्ट के तीन अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की आईडी के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। अब वीआईपी और विशेष श्रेणी के दर्शन पास ट्रस्ट के तीन अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की आईडी से ही जारी किए जाएंगे।

ट्रस्ट का मानना है कि इस नई व्यवस्था से पास जारी करने की प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुरुपयोग की संभावना को काफी हद तक रोका जा सकेगा। इस कदम से पास जारी करने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी और अनधिकृत हस्तक्षेप पर रोक लगेगी। पूर्व ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद पास जारी होने में बाधा न आए इसलिए यह फैसला लिया गया है। ट्रस्ट के मुताबिक दर्शन पास प्रणाली में तकनीकी और प्रशासनिक सुधार लगातार किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और पारदर्शी तरीके से दर्शन की सुविधा मिल सके। नई व्यवस्था इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

ट्रस्ट ने यह नई व्यवस्था पूर्व महासचिव चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉ। अनिल मिश्र और गोपाल राव की आईडी निष्क्रिय होने के बाद लागू की है। दोनों ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद श्रद्धालुओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी फिलहाल अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की निगरानी में संचालित की जा रही है। यह निर्णय पूर्व महासचिव चंपतराय व पूर्व ट्रस्टी डॉ। अनिल मिश्र एवं गोपाल राव की आईडी बंद होने के कारण लिया गया है। पहले चंपत राय और अनिल मिश्रा की आईडी से बड़ी संख्या में दर्शन पास बनते थे। दोनों ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद श्रद्धालुओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी फिलहाल अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की निगरानी में संचालित की जा रही है। अब अंतरिम महासचिव डॉ। कृष्ण मोहन की आईडी भी सक्रिय हो गई है। जिसके जरिए अब नियमित रूप से दर्शन पास जारी किए जा रहे हैं।

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए भी कोटा तय

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए भी दर्शन पास का अलग कोटा तय किया गया है। रोजाना करीब 1,800 दर्शन पास जारी किए जाते हैं, जिन्हें 6 अलग-अलग समय स्लॉट में बांटा गया है। हर स्लॉट का समय दो घंटे का होता है और उसमें करीब 300 श्रद्धालुओं को पास उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हीं स्लॉट्स के तहत विशिष्ट (VIP) और सुगम दर्शन पास भी जारी किए जाते हैं।

सीए की आईडी के जरिए दर्शन पास जारी

नई व्यवस्था के तहत ट्रस्ट द्वारा अधिकृत तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट की लॉगिन आईडी के जरिए से ही विशेष श्रेणी के दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे। इससे पास जारी करने की प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी और प्रत्येक पास का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट ने जिन तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यह जिम्मेदारी सौंपी है, उनकी डिजिटल आईडी के जरिए ही विशेष दर्शन पास जारी किए जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी को इस प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

समाज में समानता और बंधुत्व बनाने की जरूरत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के पावन उपलक्ष्य में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला कार्यालय पर श्री गुरु रविदास महाराज कलश वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ संत रविदास जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी की पवित्र माटी से भरे कलश का पूर्ण विधि-विधान, मंत्रोच्चार एवं वंदन के साथ पूजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, प्रबुद्धजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया उपस्थित सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने समाज में समानता और बंधुत्व बनाए रखने का संकल्प लिया। राज्य सभा सांसद सीमा द्विवेदी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने समाज से ऊंच-नीच, जाति-पाति और वैमनस्यता को समाप्त कर सामाजिक समरसता, भाईचारे और समानता का अमर संदेश दिया था। उनका विचार 'ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट-बड़ों सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न' आज भी हमारी नीति और चिंतन का मूल आधार है। जिला महामंत्री अजय सिंह ने कहा कि सीर गोवर्धनपुर से आई यह पवित्र माटी केवल मिट्टी नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक है पार्टी के कार्यकर्ता इस पावन कलश को जिले के प्रमुख संत-महात्माओं, मंदिरों और जन-जन तक लेकर जाएंगे तथा संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराएंगे।

पति को छोड़ घर से भागी बीवी, 6 महीने के बेटे को भी ले गई साथ...

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले स्थित गंगोह थाना क्षेत्र के दौलतपुर छन्नों गांव से एक बेहद खौफनाक और हैरतअंगेज वारदात सामने आई है। यहां इंस्टाग्राम पर हुए प्यार के चक्कर में एक मां अपने 6 महीने के मासूम बेटे समीर को लेकर अचानक लापता हो गई। पुलिस ने महिला को हापुड़ से तो सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन उसके 6 माह के मासूम बच्चे का शव मेरठ के सोहराब गेट स्थित एक नाले से बरामद हुआ। पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर मासूम बेटे की हत्या करने का संगीन आरोप लगाया है। घटनाक्रम की शुरुआत 12 जुलाई को हुई थी। पीड़ित पति इमरान के मुताबिक, 12 जुलाई को उसकी पत्नी अपने 6 महीने के बेटे समीर को साथ लेकर गंगोह कस्बे में दवा लेने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक जब मां-बेटा वापस नहीं लौटे, तो परिजनों ने हर जगह तलाश की। कोई सुराग न मिलने पर 22 जुलाई को गंगोह थाने में औपचारिक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस जांच के दौरान महिला की लोकेशन हापुड़ में ट्रैक हुई। 26 जुलाई को महिला हापुड़ जिले के मुदाफरा गांव में विशाल नाम के युवक के घर से बरामद की गई। हालांकि, उस समय उसका 6 महीने का बच्चा उसके साथ नहीं था। पूछताछ में महिला ने कुबूल किया कि कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी विशाल से जान-पहचान हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम-संबंध में बदल गई। महिला से हुई पूछताछ में बच्चे की मौत से पर्दा उठा। महिला 12 जुलाई की रात अपने बेटे को लेकर मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पर प्रेमी विशाल से मिली थी। आरोपी विशाल ने महिला से साफ कहा कि वह इस बच्चे को अपने घर नहीं ले जा सकता। इसके बाद वह बच्चे को अपने किसी दोस्त के पास सुरक्षित छोड़ने का बहाना बनाकर ले गया। अगले दिन मेरठ के सोहराब गेट इलाके के एक नाले से 6 माह के मासूम समीर का शव बरामद हुआ। आरोप है कि प्रेमी ने ही बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए नाले में फेंक दिया था।

मेरठ के नौचंदी थाने में ट्रांसफर हुई 'जीरो FIR'

सीओ (CO) शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीड़ित पति इमरान की तहरीर पर गंगोह थाने में 'जीरो एफआईआर' दर्ज कर ली गई है। क्योंकि हत्या और शव बरामदगी की मुख्य घटना मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र से जुड़ी है, इसलिए केस की पूरी फाइल और विवेचना की प्रति मेरठ पुलिस को भेजी जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

निर्माणाधीन पुलिया पर बैरियर तोड़कर बाइक टकराई, अधेड़ की मौत

सुलतानपुर। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अस्पताल भेज दिया।

पुलिस के अनुसार बालमुकुंद पांडे (45) पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण पांडे निवासी ग्राम भवानीपुर सरैया, थाना मोतीगरपुर, अपनी हीरो मोटरसाइकिल से बिरसिंहपुर रोड से बगिया चौराहे की ओर जा रहे थे। रास्ते में सपाही के पास निर्माणाधीन पुलिया पर सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरियर को बाइक ने तोड़ दिया जिसके बाद वाहन पुलिया के स्लैब से टकरा गया। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पीआरवी के माध्यम से पुलिस को मिली। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को 100 शैया अस्पताल, बिरसिंहपुर भिजवाया, जहां पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है।

नाइट ड्यूटी में छूटी पर्ची, सुबह मचा हड़कंप... अयोध्या मेडिकल कॉलेज के छात्र सरफराज ने लिखा था बम का फॉर्मूला, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मेडिकल कॉलेज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पैरामेडिकल प्रथम वर्ष के एक छात्र के पास से बम बनाने के तरीके, उसके आकार और तीव्रता से संबंधित विवरण वाली एक संदिग्ध पर्ची बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और संदिग्ध छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

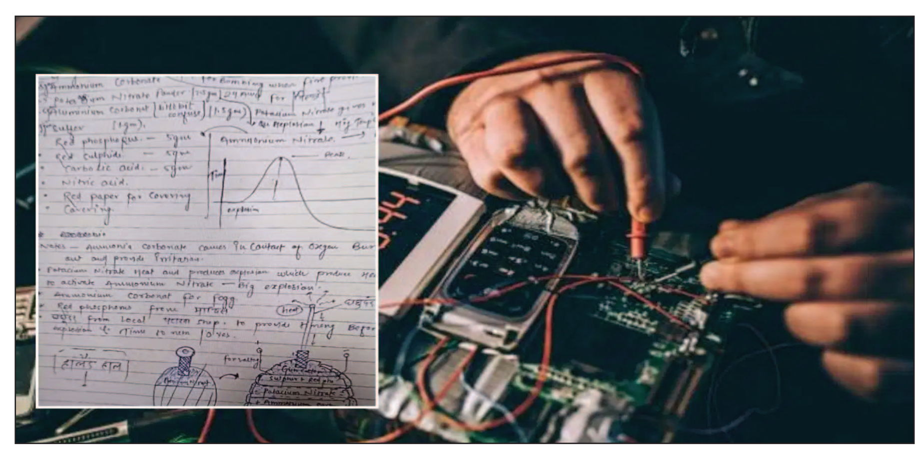

जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिले का रहने वाला छात्र सरफराज अयोध्या मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन (पैरामेडिकल) प्रथम वर्ष का छात्र है। रात के समय उसकी ड्यूटी लैब में लगी हुई थी। सुबह जब अन्य कर्मचारी और स्टाफ ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्हें लैब में एक संदिग्ध पर्ची मिली। पर्ची में लिखी बातें देखकर कर्मचारियों के होश उड़ गए और तुरंत कॉलेज प्रशासन को सूचित किया गया। जांच में पता चला कि रात में ड्यूटी सरफराज की थी और यह पर्ची उसी से गलती से छूट गई थी।

पर्ची बरामद होने के बाद पुलिस ने त्वरित जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने जब सरफराज के लैपटॉप और डिजिटल उपकरणों की जांच की, तो उसमें से भी कई संदिग्ध नोट्स और सामग्रियां बरामद हुईं। पर्ची और नोट्स में कथित रूप से बम बनाने के तरीके, उसके प्रभाव और तीव्रता से जुड़ी जानकारियां दर्ज थीं, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं।

गुप्त स्थान पर पूछताछ, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी छात्र सरफराज को तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया है। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की विशेष टीमें उसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर पूछताछ कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पर्ची का मकसद क्या था और क्या उसका संबंध किसी संदिग्ध नेटवर्क से है।

नहर किनारे मिला वृद्ध का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी

सुलतानपुर।। बल्दीराय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में नहर के किनारे एक वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वृद्ध बांस काटने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रामसुन्दर कोरी उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक चारू निगम सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली बल्दीराय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है तथा मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मृतक के परिजनो ने जमीनी विवाद को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। फिलहाल वृद्ध की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

आधार कार्ड मांगा तो 9 दिन में छोड़ी ट्रेनिंग...पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाली रुचिका का नया सच, नेल आर्ट सेंटर में बताया था फर्जी नाम

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में विवादों में आई रुचिका सिंह को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार रुचिका सिंह ने नोएडा सेक्टर 135 स्थित एक नेल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर में 3 महीने का कोर्स ज्वाइन किया था। हालांकि, संस्थान द्वारा बार-बार आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मांगे जाने पर उसने महज 9 दिन के भीतर ही ट्रेनिंग छोड़ दी। सेंटर संचालक का दावा है कि उसने यहां अपना नाम मेनिशल जैन बताया था।

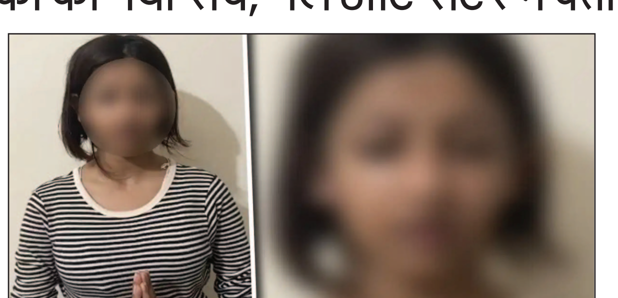

केंद्र संचालक टीपी त्रिपाठी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले रुचिका उनके सेक्टर 135 स्थित संस्थान में नेल आर्ट सीखने पहुंची थी। उसने 3 महीने के कोर्स के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रवेश के दौरान आधार कार्ड या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज जमा नहीं किए थे। संचालक का कहना है कि दस्तावेज जमा करने के लिए उसे कई बार कहा गया, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाती रही। सख्ती किए जाने के बाद उसने केवल 9 दिन में ही ट्रेनिंग छोड़ दी।

खुद को कभी नहीं बताया नीट छात्रा

सैलून संचालक ने बताया कि रुचिका ने खुद को केवल 12वीं तक पढ़ा हुआ बताया था और कभी भी यह नहीं बताया कि वह नीट परीक्षा से जुड़ी छात्रा है। संचालक का कहना है कि उसके व्यवहार पर पहले से ही उन्हें शक था, क्योंकि वह अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज देने से बच रही थी। इस मामले में गाजियाबाद की वसुंधरा निवासी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह की शिकायत पर एक्सप्रेसवे थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर थाना क्षेत्र में इस मामले को स्थानांतरित कर दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 23 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ। संबंधित पुलिस एजेंसी मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान रुचिका की पहचान को लेकर दी गई जानकारियां सामने आई हैं।

हरियाणा के फरीदाबाद की है रहने वाली

बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के ऊंचा गांव की रहने वाली है और नोएडा के सेक्टर 168 स्थित लोटस जिंक सोसाइटी में रहती थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि जब पुलिस मामले की जांच करने पहुंची तो फ्लैट पर ताला लगा मिला था, लेकिन अब उसकी असली पहचान सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उसने यह बयान जानबूझकर दिया था।

विद्युत उपकेंद्र के निर्माण का भूमि पूजन

जौनपुर। बदलापुर विधानसभा के महराजगंज क्षेत्र वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूर्ण करते हुए ग्राम भगवानपुर में बाबूगंज विद्युत उपकेंद्र के निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु भूमिपूजन विधायक रमेष चन्द मिश्र ने किया।ग्राम भगवानपुर में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बाबूगंज विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस सब स्टेशन के निर्माण से बाभनपुर, बेसार, बनबीरपुर, भगवानपुर, बाबूगंज, शेखपुर खुटहनी, केठुआ, असरोपुर, फत्तूपुर, दूधीपुर, डालूपुर, मया, पहाड़पुर, राजापुर, केवटली, धनछुआ, भवानीगढ़, सराय पड़री, एकहुआ, मनिकापुर, मुँहकुचा, अंगराह, बहाउद्दीनपुर, लोहिंदा, बिझवट, बहोरिकपुर, आनापुर, सराय दुर्गादास, अहिरौली, राजा बाजार, बनकट, सराय परशुराम, सोनपुरा, कांसापुर, भोगीपुर कठार, जगापुर समेत 40 गांवो में सुचारु बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

संक्षेप

जलार्चन के लिए कांवरियों का जत्था रवाना

जौनपुर। जफराबाद कस्बे के नावघाट मुहल्ले के गोमती नदी के घाट पर शनिवार को दर्जनों गाव के सैकड़ों कांवरिये जमा हुए।वहां से कांवरियों ने विधिवत पूजन- अर्चना करके सावन के पहले सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ धाम जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। कांवरियों के दल हर हर महादेव व हर-हर बम-बम,जय भोले के जयघोष गूंज रहा था।कांवरियों को विदाई देने काफी लोग मौजूद रहे।कांवरियों में में बच्ची यादव, सूरज मिश्रा, कमलेश प्रजापती, छट्टू प्रजापति, कल्लू प्रजापति, विकास , राहुल, प्रमोद, उमाशंकर, सहित सैकड़ों लोग रहे। कावरिया के स्वागत व उत्साहवर्धन के लिए भाजपा नेता ज्ञानप्रकाश सिंह चेयरमैन प्रतिनिधि डॉ सरफराज खान, पूर्व चेयरमैन प्रमोद बरनवाल सहित क्षेत्र के सम्मानित लोगो ने कांवरियों को पुष्प देकर उत्साहवर्धन किया।

सड़क हादसे में स्वास्थ्य कर्मी की मौत

जौनपुर। रामपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बरसठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी दीपक कुमार सरोज की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा सड़क पार कर रहे एक सांप को बचाने के प्रयास में हुआ, जब उनकी बाइक अचानक असंतुलित होकर सड़क निर्माण के दौरान बिखरी गिट्टियों और पत्थरों पर फिसल गई। दीपक कुमार सरोज किसी कार्य से बाइक द्वारा जा रहे थे। रामपुर थाना क्षेत्र के गहरोल गांव के समीप सड़क पार कर रहे एक सांप को बचाने के प्रयास में उन्होंने अचानक बाइक का संतुलन बदल दिया। इसी दौरान सड़क निर्माण सामग्री के रूप में बिखरी गिट्टियों और पत्थरों पर बाइक फिसल गई। दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने सीएचसी बरसठी परिसर में कई घंटों तक हंगामा किया और मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बताया गया कि घटना दो थाना क्षेत्रों की सीमा से जुड़ी होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर पुलिस कार्रवाई में विलंब हुआ।

कुएं में मिला अधेड़ का शव, इलाके में सनसनी

जौनपुर। केराकत थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव के रग्घूपुर पुरवा में शनिवार को एक कुएं से अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।मृतक की पहचान 45 वर्षीय राकेश शुक्ला पुत्र मानिक शुक्ला के रूप में हुई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल

जौनपुर। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के हुसैनाबाद गांव में शनिवार को जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर लाठी-डंडे चले, जिससे महिला सहित छह लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने चार घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शाहगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, हालांकि स्थिति फिलहाल पुलिस की निगरानी में सामान्य बताई जा रही है।

ग्रेटर नोएडा में 7वीं की दिव्यांग छात्रा से 4 महीने तक अश्लील हरकतें करता रहा बस ड्राइवर, सहेली ने खोला राज

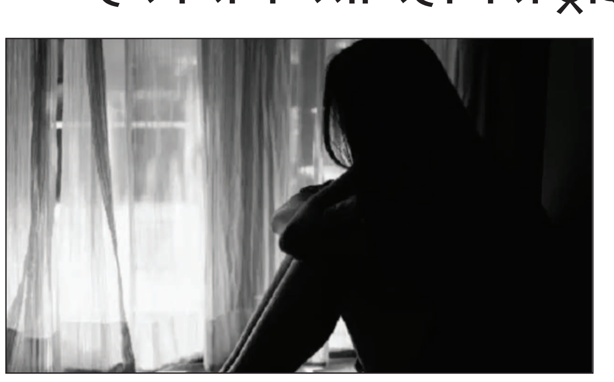

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित एक नामी निजी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 7 की 15 वर्षीय दिव्यांग छात्रा के साथ स्कूल बस ड्राइवर द्वारा लगातार 4 महीने तक अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा की एक सहेली ने आरोपी ड्राइवर की हरकत देख ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर लव कुश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

वहीं स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर ड्राइवर की नियुक्ति और पुलिस सत्यापन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। पीड़िता के पिता के अनुसार, उनकी बेटी बचपन से ही सुनने में असमर्थ है और स्कूल की बस से आना-जाना करती है। अप्रैल महीने में मेरठ में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता के लिए स्कूल की टीम के साथ जाते समय आरोपी ड्राइवर ने पहली बार छात्र के साथ अशोभनीय हरकत की। विरोध करने पर उसने इशारों में छात्रा को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे छात्रा डर गई और उसने कई महीनों तक किसी को कुछ नहीं बताया।

परिजनों का आरोप है कि स्कूल बस में अन्य बच्चों को पहले उतारने के बाद वह छात्रा को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। कभी उसे गलत तरीके से छूता था तो कभी इशारों से अपने पास बुलाता और एक बार उसका पैर पकड़कर भी अश्लील हरकत की। लगातार उत्पीड़न के कारण छात्रा मानसिक तनाव में रहने लगी और कुछ दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है।

स्कूल प्रबंधन को भेजा गया नोटिस

26 जुलाई को जब दोबारा हरकत ड्राइवर द्वारा की गई तो उसकी सहेली ने यह सब होता वह देख लिया। इसके बाद प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की गई। जब छात्रा के परिजनों को यह बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। थाना प्रभारी नॉलेज पार्क विनोद कुमार ने बताया कि स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर ड्राइवर की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन और अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं। साथ ही स्कूल की सीसीटीवी फुटेज खगली जा रही है। जांच टीम शिक्षकों कर्मचारियों बस स्टॉफ और अन्य लोगों के बयान में दर्ज करेगी ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

शिकायतों के बावजूद तालाब की जमीन से नहीं हटा अवैध कब्जा

» तहसील प्रशासन पर उदासीनता के आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय, सुल्तानपुर। तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोभियारा में सार्वजनिक तालाब की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर चर्चा में है। शिकायतकर्ता धनई का आरोप है कि गांव के निवासी उमा शंकर द्वारा तालाब की जमीन पर कब्जा किया गया है, जिससे ग्रामीणों को सार्वजनिक भूमि का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार तहसील समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कथित कब्जा नहीं हटाया गया। शिकायत कर्ता का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर यदि अतिक्रमण बना रहता है तो जल संरक्षण की व्यवस्था प्रभावित होती है और भविष्य में गांव को जल संकट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका आरोप है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण कथित कब्जाधारी के हौसले बुलंद हैं। शिकायत कर्ता ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बनता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए खतरा?

इंसुलिन रेजिस्टेंस को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर इसका खतरा शरीर में पैदा हो जाए तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है। एक्सपर्ट से जानें ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है?

जब लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब सिर्फ डायबिटीज है। लेकिन सच ये है कि इसका असर डायबिटीज होने से पहले ही दिल और खून की नसों पर पड़ना शुरू हो सकता है। आसान भाषा में समझें तो इंसुलिन एक हार्मोन है, जो खून में मौजूद शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ताकि उससे शरीर को एनर्जी मिल सके।

लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात ठीक से नहीं मानतीं। ऐसे में पैंक्रियास, ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। जब लंबे समय तक शरीर में इंसुलिन का स्तर ज्यादा बना रहता है, तो इसका असर धीरे धीरे दिल और खून की नसों पर भी पड़ने लगता है।

हाई ब्लड प्रेशर का खतरा

डॉक्टर प्रिया कंसलटेंट, एंड्रोक्रिनोलॉजी का कहना है कि सबसे पहले खून की नसों की अंदरूनी परत ठीक से काम नहीं करती। नसें पहले जितनी लचीली नहीं रहतीं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL कम होने लगता है। शरीर में हल्की हल्की सूजन भी बनी रहती है और ऐसे हानिकारक तत्व बनने लगते हैं, जो खून की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। समय के साथ इन नसों में चर्बी जमने लगती है। इससे नसें संकरी और सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल और दिमाग तक खून का बहाव कम हो सकता है। यही वजह है कि आगे चलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

इसे कैसे किया जा सकता है ठीक?

अच्छी बात ये है कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का समय रहते पता चल जाए, तो इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। नियमित एक्सरसाइज, वजन को कंट्रोल में रखना और संतुलित खाना खाना, ये तीन चीजें आपके ब्लड शुगर के साथ साथ दिल को भी लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।

बैलेंस डाइट में हरी सब्जियां, सीजन फल और फाइबर वाली चीजें खानी चाहिए। फाइबर के लिए ओट्स जैसी चीजें खाई जा सकती हैं। इससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है और आप ओवरईटिंग से भी बच पाते हैं।

दिल के मरीज हैं तो एक्सपर्ट की सलाह पर अपनी फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो करें। वैसे हर किसी को रोजाना कम से कम 30 मिनट की सैर जरूर करनी चाहिए।

सबसे जरूरी है कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को न बढ़ने दें। नसों में कोलेस्ट्रॉल के जमने से ब्लड फ्लो बिगड़ता है और हार्ट अटैक के आसार बन जाते हैं।

दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है अच्छी नींद

दिल को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद न लेने से दिल से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं अच्छी नींद लेने से दिल को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

दिल हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। दिल की अच्छी सेहत के लिए लोग अक्सर हेल्दी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अच्छी नींद को नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल काम का दबाव, तनाव या देर रात तक मोबाइल चलाने की वजह से कई लोग पूरी नींद नहीं ले पाते। इसका असर सिर्फ थकान या सुस्ती तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे-धीरे दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है।

अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, अच्छी नींद दिल को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। लंबे समय तक पूरी नींद न लेने से हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए स्वस्थ दिल के लिए हर दिन पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी माना जाता है, जितना सही खानपान और शारीरिक एक्टिविटी करना। आइए जानते हैं अच्छी नींद लेने से हार्ट को क्या फायदे मिलते हैं, कितनी नींद लेनी चाहिए और अच्छी नींद लेने के लिए क्या किया जा सकता है।

अच्छी नींद लेने से हार्ट को क्या फायदे मिलते हैं?

CDC के मुताबिक, अच्छी नींद दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब हम पूरी नींद लेते हैं, तो शरीर को आराम मिलता है और दिल को भी बेहतर तरीके से काम करने का समय मिलता है। पर्याप्त नींद ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह शरीर के वजन को संतुलित रखने और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में भी मदद करती है।

अच्छी नींद लेने से शरीर में होने वाली कई ऐसी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है, जो आगे चलकर दिल की बीमारियों की वजह बनती हैं। यही कारण है कि स्वस्थ दिल के लिए अच्छी नींद को हेल्दी खानपान और शारीरिक एक्टिविटी जितना ही जरूरी माना जाता है।

कितनी नींद लेने से दिल को मिल सकता है फायदा?

एडल्ट्स को हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त नींद लेने से दिल और शरीर दोनों बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक 7 घंटे से कम सोता है, तो दिल से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

इसलिए कोशिश करें कि रोज पर्याप्त नींद लें और सोने व उठने का समय लगभग एक जैसा रखें। इससे शरीर की प्राकृतिक नींद की प्रक्रिया बेहतर रहती है और दिल की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ सकता है।

अच्छी नींद लेने के लिए क्या करें?

अच्छी नींद के लिए सोने का माहौल शांत, साफ और आरामदायक रखें। सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का इस्तेमाल कम करें। शाम के समय ज्यादा चाय, कॉफी या कैफीन वाले ड्रिंक पीने से बचें। रात में बहुत भारी खाना खाने की बजाय हल्का भोजन करें।

दिन में थोड़ी शारीरिक एक्टिविटी करने से भी रात में अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है। अगर आपको लंबे समय से नींद नहीं आती या बार-बार नींद टूटती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

जेन जी की भाषा ट्रेंड में, जानें क्लॉक इट, डेलुलु और फोमो का मतलब

संसद में जेन जी की भाषा का जिक्र होने के बाद क्लॉक इट, डेलुलु और फोमो जैसे शब्द चर्चा में हैं। ये शब्द सोशल मीडिया पर खूब इस्तेमाल होते हैं। आइए जानते हैं इनका आसान मतलब क्या है।

संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने अपने भाषण में Clocked It, Delulu, FOMO, M।I।A। और वास्ते गुना हुइया जैसे Gen-Z स्लैंग्स का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर अक्सर सुनाई देने वाले ये शब्द जब संसद में गूंजे, तो इनकी चर्चा हर तरफ होने लगी। पहली बार इतने बड़े स्तर पर Gen-Z की भाषा संसद की कार्यवाही में सुनाई दी। Gen-Z यानी आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और रोजमर्रा की बातचीत में ऐसे स्लैंग्स का खूब इस्तेमाल करती है। ये शब्द छोटे होते हैं, लेकिन इनके अलग-अलग मतलब होते हैं।

संसद में भी इनका इस्तेमाल युवाओं, पेपर लीक आंदोलन और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए किया गया। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि इन शब्दों का मतलब क्या है और सांसदों ने इन्हें किस संदर्भ में कहा। आइए जानते हैं संसद में चर्चा में आए इन Gen-Z स्लैंग्स के बारे में।

मंगलवार को संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने Gen-Z की भाषा का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में FOMO और M।I।A। जैसे शब्द बोले। वहीं, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सरकार का पक्ष रखते हुए Clocked It कहा।

तेजस्वी सूर्या और श्रीकांत शिंदे ने Delulu और FOMO का इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वास्ते गुना हुइया का जिक्र किया। एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपने भाषण में Delulu शब्द का इस्तेमाल किया। सत्ता और विपक्ष, दोनों के सांसदों की जुबान पर Gen-Z के ये शब्द सुनाई दिए, जिसके बाद इनकी खूब चर्चा होने लगी।

Clocked It, Delulu, FOMO और M।I।A। का क्या मतलब है?

संसद में इस्तेमाल हुए Gen-Z के इन शब्दों का मतलब अलग-अलग है।

Clocked It का मतलब है किसी बात या स्थिति को सही तरीके से समझ लेना।

Delulu शब्द Delusion से बना है। इसका मतलब होता है किसी गलतफहमी या भ्रम में रहना।

FOMO का पूरा नाम Fear Of Missing Out है, यानी किसी मौके या घटना से छूट जाने का डर।

M.I.A. का मतलब Missing In Action होता है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जो लंबे समय तक दिखाई न दे या किसी काम में शामिल न हो।

आजकल सोशल मीडिया पर ये शब्द काफी आम हो चुके हैं। युवा बातचीत, मीम्स और रील्स में इनका खूब इस्तेमाल करते हैं। अब यही शब्द संसद की बहस का भी हिस्सा बन गए।

वास्ते गुना हुइया क्या है, जिसकी संसद में भी हुई चर्चा?

संसद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने भाषण के दौरान वास्ते गुना हुइया का जिक्र किया। यह सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक मीम और ट्रेंडिंग फ्रेज है। इसका कोई तय या आधिकारिक मतलब नहीं है, लेकिन लोग इसे मजाक या हल्के-फुल्के अंदाज में इस्तेमाल करते हैं।

बताया जाता है कि इसकी शुरुआत कई साल पहले वायरल हुए एक वीडियो और इंटरनेट मीम से हुई थी। समय के साथ यह अलग-अलग रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट में नए अंदाज में इस्तेमाल होने लगा। आज कई कंटेंट क्रिएटर भी इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है।

सोशल मीडिया की भाषा संसद तक कैसे पहुंची?

Gen-Z की भाषा पहले सोशल मीडिया, मीम्स और रील्स तक ही सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब इसका असर राजनीति में भी दिखने लगा है। पेपर लीक आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा जुड़े थे और सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे थे। ऐसे में कई सांसदों ने भी युवाओं से जुड़ने और अपनी बात आसान तरीके से समझाने के लिए Gen-Z के स्लैंग्स का इस्तेमाल किया।

यही वजह है कि पहली बार संसद की बहस में इतने Gen-Z शब्द सुनाई दिए। इससे साफ है कि सोशल मीडिया की भाषा अब धीरे-धीरे सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चाओं का भी हिस्सा बनती जा रही है।

आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन आज! जानिए क्या है 30 दिनों वाला 'ई-वेरिफिकेशन' का खास नियम

जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल करते हैं, वे 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वेरिफिकेशन की डेडलाइन फाइलिंग की तारीख, देर से भरे गए रिटर्न के स्टेटस और इनकम टैक्स नियमों के पालन पर कैसे असर डालती है।

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और ई-वेरिफाई कर लिया है? अगर नहीं, तो आज ऐसा करने का आखिरी दिन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आज, 31 जुलाई को आखिरी समय में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का यह आखिरी दिन है।

योग्य टैक्सपेयर्स के लिए, नियमों का पालन करने के लिए तय डेडलाइन से पहले फाइल करना जरूरी है। सिर्फ ITR फॉर्म अपलोड करना काफी नहीं है। इनकम टैक्स रूल्स के तहत रिटर्न को मान्य मानने के लिए ई-वेरिफिकेशन जरूरी है।

अच्छी खबर यह है कि आज ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को तुरंत ई-वेरिफिकेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है। कानून में वेरिफिकेशन के लिए एक अलग डेडलाइन दी गई है, जो कुछ शर्तों के अधीन है।

क्या डेडलाइन के बाद ITR वेरिफाई कर सकते हैं?

हां, नियमों के अनुसार, अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई को या उससे पहले ITR फाइल करता है, तो उसे उसी तारीख को फाइल किया हुआ माना जाएगा, बशर्ते अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन पूरा हो जाए।

इसका मतलब है कि आज ITR फाइल करने वाला व्यक्ति अगस्त में ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकता है, जिससे ओरिजिनल फाइलिंग की तारीख पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते तय 30 दिनों की अवधि के भीतर वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाए।

हालांकि, 30 दिनों से ज्यादा की देरी का मतलब है कि वेरिफिकेशन की तारीख ही फाइलिंग की तारीख बन जाएगी, जिससे रिटर्न को 'बिलेटेड' (देरी से फाइल किया गया) माना जा सकता है। अगर 31 दिसंबर तक वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है, तो रिटर्न को अमान्य माना जा सकता है।

30-दिन के नियम के तहत क्या स्थितियां हैं?

सिनेरियो	टैक्स ट्रीटमेंट
31 जुलाई को ITR फाइल किया और 30 दिनों के भीतर वेरिफाई किया	31 जुलाई की ओरिजिनल फाइलिंग तारीख मान्य रहती है
31 जुलाई को ITR फाइल किया लेकिन 30 दिनों के बाद वेरिफाई किया	वेरिफिकेशन की तारीख फाइलिंग की तारीख बन सकती है; रिटर्न को 'बिलेटेड' माना जा सकता है
आखिरी स्वीकार्य तारीख (31 दिसंबर, 2026) तक ITR वेरिफाई नहीं किया	रिटर्न को अमान्य माना जा सकता है, जब तक कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देरी को माफ़ न कर दे।

टैक्सपेयर्स को वेरिफिकेशन में देरी से क्यों बचना चाहिए?

ज्यादातर टैक्सपेयर्स आधार OTP, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। जो टैक्सपेयर्स इनमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें साइन किए हुए ITR-V को जमा करने के लिए तय प्रोसेस का पालन करना होगा।

हालांकि टैक्स के नियम आज की फाइलिंग डेडलाइन के बाद भी वेरिफिकेशन की इजाजत देते हैं, फिर भी सभी टैक्सपेयर्स को बेवजह देरी से बचना चाहिए। इससे यह पक्का होगा कि रिटर्न आसानी से प्रोसेस हो जाए, ओरिजिनल फाइलिंग की तारीख बनी रहे और रिटर्न को 'देरी से भरा गया' (belated) या 'अमान्य' (invalid) माने जाने का रिस्क कम हो।

चूंकि फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई आज खत्म हो रही है, इसलिए टैक्सपेयर्स को कट-ऑफ से पहले अपना रिटर्न जमा कर देना चाहिए और अगले 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहिए। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www lincometax lgov lin/iec /foportal/ पर जाएं।

बैंक की इस सीक्रेट सर्विस से बिना कुछ किए खाते में मिलेगा 3 गुना ब्याज, तुरंत जानें तरीका

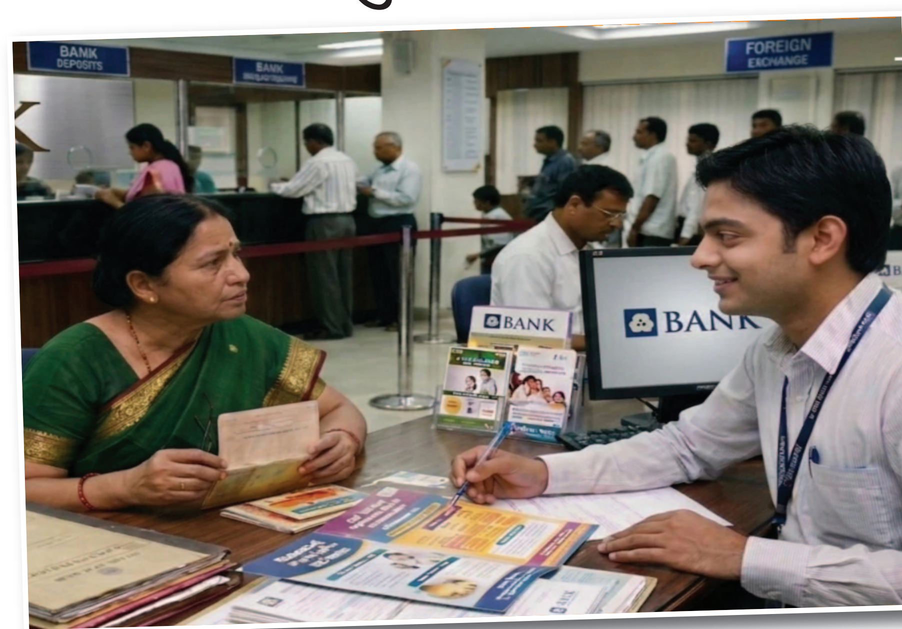

नई दिल्ली, एजेंसी। जब भी आप किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो बैंक कर्मचारी आपको एटीएम, डेबिट कार्ड और खाते पर मिलने वाले साधारण ब्याज की जानकारी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंकों की एक ऐसी खास और सीक्रेट सर्विस भी है जो आपके सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को सीधा तीन गुना तक बढ़ा सकती है। इस सर्विस के जरिए आपको अपने साधारण बचत खाते पर भी फिक्स्ड डिपॉजिट जितना शानदार ब्याज मिल सकता है। हैरानी की बात यह है कि बैंक में खाता खुलवाने वाले हर ग्राहक को मिलने वाली इस धांसू सुविधा के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको केवल बैंक जाकर इसे इनेबल करने के लिए कहना होता है।

क्या है बैंक ऑटो स्वीप सर्विस का जादुई फॉर्मूला?

हम जिस खास सुविधा की बात कर रहे हैं, उसे बैंकिंग की भाषा में 'बैंक ऑटो स्वीप सर्विसÓ कहा जाता है। यह एक ऐसी कमाल की फैसिलिटी है जो ग्राहकों को उनके सरप्लस फंड पर अधिकतम ब्याज दिलाने में मदद करती है। इस सर्विस को अपने खाते में इनेबल कराने के बाद, अगर आपके सेविंग अकाउंट में जमा राशि एक तय लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो वह अतिरिक्त पैसा ऑटोमैटिक तरीके से एफडी में ट्रांसफर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस ट्रांसफर हुए अतिरिक्त पैसे पर आपको साधारण बचत खाते के बजाय बैंक एफडी के हिसाब से तगड़ा ब्याज मिलने लगता है।

कैसे काम करता है ऑटो स्वीप का पूरा गणित?

इस सर्विस का गणित बेहद आसान है और यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक काम करती है। इसे एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि आपने अपने बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये की ऑटो स्वीप लिमिट सेट करवा दी और किसी दिन आपने खाते में 80,000 रुपये जमा कर दिए। ऐसे में ऑटो स्वीप सर्विस तुरंत एक्टिव हो जाएगी और लिमिट से ऊपर का 60,000 रुपये का अमाउंट अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको इस 60,000 रुपये पर एफडी के हिसाब से ज्यादा ब्याज मिलेगा, जबकि बाकी बचे 20,000 रुपये पर सेविंग अकाउंट का सामान्य ब्याज मिलता रहेगा। इसके लिए आपको खुद से एफडी कराने के झंझट में नहीं पड़ना होता है।

एफडी से ज्यादा फायदेमंद कैसे है ये धांसू सुविधा?

आमतौर पर बैंक सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर औसतन 2.5 फीसदी के आसपास ब्याज देते हैं, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर यह ब्याज दर 6.5 से 7 फीसदी तक होती है। ऑटो स्वीप सर्विस शुरू होते ही आपको अपने बचत खाते पर लगभग तीन गुना ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है, जिससे आपकी नियमित बचत में तेजी से इजाफा होता है। इस सुविधा की सबसे खास बात यह है कि आपको ब्याज तो एफडी का मिलता है, लेकिन आप अपने खाते को बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर आप एफडी में कन्वर्ट हुए पैसे को मैच्योरिटी पीरियड से पहले कभी भी निकाल सकते हैं, जो कि सामान्य एफडी में मुमकिन नहीं होता है।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने कितने भारतीयों को भेजा वापस? सामने आया ये आंकड़ा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को लगातार देश वापस भेजा जा रहा है. अमेरिका ने 2025 से अब तक कुल 4,840 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है. इनमें इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 1,273 लोग भेजे गए हैं. विदेश मंत्रालय ने की तरफ से इसकी जानकारी दी गई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, एक जनवरी 2026 से अब तक अमेरिका से भारत वापस भेजे गए भारतीयों की कुल संख्या 1,273 है. 2025 में कुल 3,567 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया था.

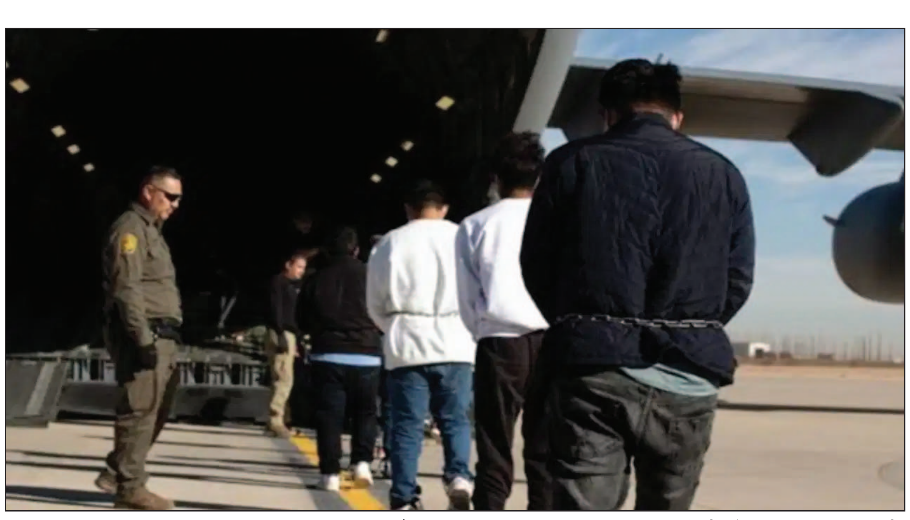

जायसवाल ने ये बात अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कही. उन्होंने बताया कि भारत निर्वासन से जुड़े मामलों पर कई देशों की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है. उन्होंने कहा, जब भी कोई ऐसा मामला हमारे पास आता है, तो हम पहले खुद जांच करते हैं कि वो व्यक्ति वाकई भारतीय नागरिक है या नहीं."

कब होती है भारत आने की व्यवस्था?

रणधीर जयसवाल ने कहा, एक बार जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि संबंधित व्यक्ति भारतीय नागरिक है, तभी हम उनकी भारत वापसी की व्यवस्था करते हैं." अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़े अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को निर्वासित कर रहा है.

भारतीयों के साथ गलत व्यवहार पर हुआ था विरोध

भारत से वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों के साथ किए जाने वाले बर्ताव का मुद्दा भी भारत सरकार की प्राथमिकता रहा है. पिछले साल दिसंबर में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद को बताया था कि नई दिल्ली ने अमेरिकी अधिकारियों से बात की है ताकि ये पक्का किया जा सके कि वापस भेजे जा रहे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो. भारत ने खास तौर पर यह अनुरोध किया था कि वापस भेजे जाने वाली उड़ानों के दौरान महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी या जंजीरों से न बांधा जाए. ये चिंताएं तब और बढ़ गईं जब 2025 में 73 साल हरजीत कौर को देश से वापस भेजे जाने के दौरान उनके साथ बुरा बर्ताव किए जाने की खबरें सामने आईं. इसके अलावा, पिछले साल फरवरी में देश से वापस भेजने वाली एक फ़्लाइट में महिलाओं और बच्चों को बेड़ियों या बंधन में रखने की घटना की भी काफी आलोचना हुई. इसके बाद भारत ने अमेरिकी सरकार के सामने औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराया.

पाकिस्तान के लयारी में गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई को मारी गोली, हालत गंभीर

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तानी गैंगस्टर और पीपुल्स अमन कमेटी के प्रमुख और जेल में बंद उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच को गुरुवार शाम कराची के लयारी में गोली मार दी गई। जुबैर बलोच की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, उसे सीने और पेट में गोली लगी है, जिसके बाद उसे शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस गोलीबारी में दो राहगीरों के भी घायल होने की सूचना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने जवाबी फायरिंग किए जाने पर अपने चेहरे ढक लिए और भाग गए। इस मामले में सीनियर पुलिस अधिकारी सैयद असद रजा ने बताया कि जुबैर उस समय अपने घर के बाहर था।

खबरों के मुताबिक, जुबैर बलोच को साल 2012 में गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल जनवरी में उसे रिहा भी कर दिया गया था। पाकिस्तान पुलिस गैंगवार और आपसी दुश्मनी समेत कई पहलुओं से घटना की जांच कर रही है।

लयारी के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने डॉन को बताया कि जुबैर बलोच कुछ महीने पहले ही एक 'राजनीतिक पार्टी' में शामिल हो गया था और उसने इलाके में उसके झंडे फहराए थे। कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि ऐसी अफवाहें थीं कि 'कराची ऑपरेशन' के बाद दुबई और ईरान भाग गए कुछ गैंगस्टर अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद वापस लौट आए हैं। वहीं, लयारी के निवासी इस बात को लेकर चिंता में पड़ गए हैं कि कहीं फिर से गैंगवार तो नहीं शुरू हो गया।

अमेरिका का 11 करोड़ डॉलर का F–35B विमान क्रैश, पायलट पर क्या बोली सेना?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका का अत्याधुनिक F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान शुक्रवार को कैलिफोर्निया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अच्छी बात यह रही कि विमान के पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स ने बताया कि पायलट को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उसकी हालत स्थिर है और उसे गंभीर चोट नहीं आई है। एक F-35B की कीमत करीब 10।9 करोड़ डॉलर (1040 करोड़ रुपये) है।

यह हादसा कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार के पास हुआ। दुर्घटना के बाद घटनास्थल से काले धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। हेलिकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में कई सैन्य वाहन, दमकल की गाड़ियां और राहतकर्मी मौके पर काम करते नजर आए। आग बुझाने के लिए जमीन पर सफेद रंग का अग्निरोधी रसायन (फ्लेम रिटार्डेंट) डाला गया और दमकलकर्मियों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया।

हादसे की जांच मरीन कॉर्प्स करेगी

सैन डिएगो फायर विभाग की प्रवक्ता कैंडेस हैडली ने बताया कि विमान गिरने के बाद आसपास की झाड़ियों में आग लग गई थी। दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हादसे की जांच अब मरीन कॉर्प्स कर रही है। मिरामार एयरबेस पहले अमेरिकी नौसेना के मशहूर 'टॉप गन' फाइटर पायलट ट्रेनिंग स्कूल का केंद्र था। उस समय इसे 'फाइटरटाउन यूएसए' कहा जाता था। बाद में 1996 में इस ट्रेनिंग स्कूल को नेवादा के नेवल एयर स्टेशन फॉलन में ट्रांसफर कर दिया गया।

US के पास 630 से ज्यादा F-35 विमान

अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, नौसेना और वायुसेना के पास मिलाकर 630 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान हैं। F-35B इस विमान का ऐसा मॉडल है, जो कम दूरी से उड़ान भर सकता है और जरूरत पड़ने पर सीधा ऊपर-नीचे उतर सकता है। अमेरिकी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, F-35 कार्यक्रम पर कुल करीब 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है। इसमें 1,800 से ज्यादा नए विमान खरीदने और कई दशकों तक उनके संचालन का खर्च भी शामिल है। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन के एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अनुसार, 2026 में अब तक अमेरिका में कम से कम सात अन्य सैन्य विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा हादसा जून में कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में हुआ था, जहां उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक B-52 बॉम्बर विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार आठों लोगों की मौत हो गई थी।

10 साल में सबसे नीचे पहुंची अमेरिकी पासपोर्ट की रैंकिंग, भारत 81वें स्थान पर

वॉशिंगटन, एजेंसी। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग बताने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। इस बार अमेरिकी पासपोर्ट पिछले 10 साल में अपनी सबसे निचली रैंकिंग पर पहुंच गया है। अब 30 से ज्यादा देशों के पासपोर्ट अमेरिका से आगे निकल चुके हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी पासपोर्ट कमजोर हो गया है। असल वजह यह है कि कई दूसरे देशों ने अपने नागरिकों के लिए ज्यादा देशों में बिना वीजा या वीजा-ऑन-अराइवल के यात्रा की सुविधा हासिल कर ली है। भारत की बात करें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 81वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले लोग 55 देशों में बिना पहले से वीजा लिए यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल भारत 85वें स्थान पर था, इसलिए इस बार उसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। हालांकि वीजा-फ्री देशों की संख्या 57 से घटकर 55 हो गई है। इसका कारण कुछ देशों की बदली हुई वीजा नीति है, न कि भारत के लिए नए देशों का जुड़ना।

199 देशों के पासपोर्ट का आकलन

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे चर्चित पासपोर्ट रैंकिंग में से एक है। इसमें 199 देशों के पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों का आकलन किया जाता है। रैंकिंग इस आधार पर तय होती है कि किसी देश के नागरिक बिना पहले से वीजा लिए या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा के साथ कितने देशों में जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के वर्षों में कई देशों ने नए समझौते किए हैं और दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। इसके चलते उनके नागरिकों को ज्यादा देशों में वीजा-फ्री यात्रा की सुविधा मिली है। इसी वजह से कई देश अमेरिका से आगे निकल गए हैं। अब अमेरिकी नागरिकों को पहले की तुलना में ज्यादा देशों की यात्रा के लिए पहले से वीजा या ट्रैवल ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। यह रैंकिंग किसी देश की आर्थिक ताकत या राजनीतिक प्रभाव नहीं, बल्कि केवल यात्रा की आजादी को दिखाती है।

सिगापुर का पासरपोर्ट सबसे ताकतवर

इस साल भी सिंगापुर दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना हुआ है। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि स्वीडन तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्पेन भी सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देशों में शामिल हैं। वहीं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीस भी टॉप-10 देशों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 यह दिखाता है कि आज के समय में किसी देश के नागरिकों को कितने देशों में आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलती है, यह उसकी वैश्विक पहुंच का बड़ा पैमाना बन गया है। अमेरिका का पासपोर्ट अब भी दुनिया के मजबूत पासपोर्टों में शामिल है, लेकिन दूसरे देशों ने वीजा-फ्री यात्रा बढ़ाने की दिशा में उससे तेज़ी से प्रगति की है।

वाहनों के धुएं से हर साल 90 हजार मौतें, जीरो-एमिशन से बदल सकती है तस्वीर

नई दिल्ली। भारत की सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं सिर्फ हवा को ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को भी लील रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वाहन प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल करीब 90 हजार लोगों की असमय मौत हो जाती है और 15,300 बच्चों में अस्थमा के नए मामले सामने आते हैं। यानी हर छह मिनट में एक व्यक्ति की जान जा रही है और हर 34 मिनट में एक बच्चा अस्थमा का शिकार हो रहा है। लेकिन इस भयावह तस्वीर के बीच रिपोर्ट एक उम्मीद भी जगाती है। अगर देश जीरो-एमिशन वाहनों की ओर तेजी से कदम बढ़ाए, तो 2050 तक करीब 17 लाख असमय मौतों को टाला जा सकता है।

"Health benefits of zero-emission transport through 2050" नाम की इस रिपोर्ट में एक ऐसा परिदृश्य तैयार किया गया है, जिसमें 2045 तक बिकने वाले सभी नए वाहन जीरो-एमिशन श्रेणी के हों। इस मॉडल के जरिए हवा की गुणवत्ता, असमय मौतों और बच्चों में अस्थमा पर पड़ने वाले असर का आकलन किया गया। नतीजे चौंकाने वाले हैं। वाहन उत्सर्जन से जुड़ी वैश्विक असमय मौतों में अकेले भारत की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में वाहन प्रदूषण की समस्या न सिर्फ गंभीर है, बल्कि दुनिया के मुकाबले असंगत रूप से ज्यादा भी है। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या इस समस्या को और उलझा रही है, खासकर उन शहरों में जहां ट्रैफिक घनत्व पहले से ही चरम पर है।

बच्चों पर सबसे ज्यादा असर

रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर को इस संकट का सबसे बड़ा केंद्र बताया गया है। 2024 में अकेले एनसीआर में वाहन प्रदूषण से जुड़ी 8,100 असमय मौतें दर्ज हुईं, जो देश के कुल आंकड़े का 9 प्रतिशत है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि एनसीआर में बच्चों में अस्थमा के 3,500 नए मामले सामने आए, जो पूरे देश के मामलों का 23 प्रतिशत है। जबकि यहां की आबादी देश की कुल आबादी का महज 5 प्रतिशत ही है। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो यहां 2024 में वाहन प्रदूषण से 2,800 असमय मौतें और 1,500 बच्चों में अस्थमा के नए मामले दर्ज किए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादा प्रदूषण वाले शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चे रोजाना स्कूल आने-जाने और सामान्य गतिविधियों के दौरान बार-बार ट्रैफिक से जुड़े प्रदूषण के संपर्क में आते हैं, जिससे उनके फेफड़ों पर असर पड़ता है। एनसीआर के कुछ बेहद प्रदूषित इलाकों में तो सिर्फ वाहनों से निकलने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही WHO के तय सालाना मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पार कर गया, जबकि यह मानक सभी स्रोतों से मिलकर बनने वाले कुल प्रदूषण के लिए तय किया गया है। दिल्ली में वाहनों से जुड़े PM2.5 के संपर्क का औसत स्तर 2024 में 13 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो WHO के कुल PM2।5 मानक से ढाई गुना से भी ज्यादा है।

ट्रकों-बसों का सबसे बड़ा योगदान

रिपोर्ट में एक अहम पहलू यह भी सामने आया कि भारी वाहन यानी ट्रक और बसें, भले ही कुल वाहन बेड़े में इनकी संख्या कम हो, लेकिन प्रदूषण फैलाने में इनका योगदान सबसे ज्यादा है। 2024 में इन्हीं भारी वाहनों से सड़क परिवहन क्षेत्र का 79 प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन और 64 प्रतिशत PM2.5 उत्सर्जन हुआ। यानी अगर नीति-निर्माताओं को असर दिखाना है, तो सबसे पहले भारी वाहनों के इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान देना होगा। ICCT में भारत के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि टेलपाइप उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म करने का एकमात्र रास्ता इलेक्ट्रिफिकेशन ही है।

उनके मुताबिक भारत को टिकाऊ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ हासिल करने के लिए कम और शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को अपनाने की रफ्तार बढ़ानी होगी, पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सिस्टमैटिक तरीके से हटाना होगा और परिवहन नीतियों को सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित न रखकर पूरे देश में मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट एक चेतावनी और एक रास्ता, दोनों साथ पेश करती है।

चेतावनी यह कि वाहन प्रदूषण से हर साल हजारों जानें जा रही हैं और लाखों बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। रास्ता यह कि अगर भारत ने समय रहते जीरो-एमिशन वाहनों की तरफ ठोस और तेज कदम उठाए, तो आने वाले दशकों में लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।

कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों को मिलेगा 16-16 लाख का मुआवजा, सीएम उमर का ऐलान

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले में दो गैर-स्थानीय मजदूरों की मौत हो गई। दोनों ही मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। दहशतगर्दों की इस कायराना हरकत की सूबे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ी निंदा करते हुए दुख जाहिर किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय का तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें कहा गया है 'मुख्यमंत्री ने कुलगाम में दो मजदूरों की जघन्य हत्या की कड़ी निंदा की है और निर्दोषों की जान जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है'। इसके साथ ही ज़िला प्रशासन की ओर से भी पाड़ित परिवारों को 6-6 लाख की तत्काल सहायता देने का ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिया कि सरकार इस मुश्किल समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

'शादी कर लो लाइफ बन जाएगी...', किसने दिया राघव जुयाल को प्रपोजल? अजीब चीजों के लिए लोग मांगते हैं पैसे

इन दिनों राघव जुयाल का नाम शहनाज गिल के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि दोनों एक-दूसरे को दोस्त बताते हैं। हाल ही में राघव जुयाल ने बताया कि उन्हें कौन शादी के लिए प्रपोजल भेजता है?

इन दिनों राघव जुयाल फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' की वजह से चर्चा में हैं। बीते दिनों इस फिल्म को लेकर उन्होंने कई इंटरव्यू दिए, इसी दौरान बताया कि सोशल मीडिया पर उन्हें शादी के प्रपोजल मिलते हैं, लड़कियां अजीब और अटपटे मैसेज लिखकर भेजती हैं। साथ ही कुछ अन्य लोग भी अजीब-अजीब चीजों के लिए उन्हें पैसे मांगते हैं।

कौन भेजता है शादी के लिए प्रपोजल?

इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए गए एक इंटरव्यू में राघव कहते हैं, 'मुझे लड़कियां सोशल मीडिया पर डीएम करती हैं, मैसेज करती हैं कि मुझसे शादी कर लो लाइफ बन जाएगी।मैं सोचता हूं कि ऐसी कौन सी लड़की है कि जिससे शादी करके लाइफ बन जाएगी।'

राघव जुयाल आगे कहते हैं, 'कई लोग तो शराब पीने के लिए मुझसे सोशल मीडिया पर पैसे मांगते हैं। कहते हैं कि आज मौसम अच्छा पैसे भेज दो।'

क्यों जुड़ा था शहनाज गिल और राघव जुयाल का नाम?

राघव ने तो शादी वाली बात मजाक में कही लेकिन इन दिनों करीबी दोस्त शहनाज गिल के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। सवाल है कि आखिर इनका नाम क्यों एक-साथ जोड़ा गया। तो बता दें कि राघव जुयाल और शहनाज गिल ने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में साथ काम किया था। फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने दोनों की केमिस्ट्री को लेकर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की थी। इसके बाद दोनों के डेटिंग की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि, बाद में राघव जुयाल ने इन चर्चाओं पर सफाई देते हुए कहा था कि सलमान खान ने सिर्फ मजाक किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके और शहनाज के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था।

बर्थ डे पार्टी में साथ दिखे

हाल ही में दोनों राघव की बर्थ डे पार्टी में साथ दिखे। यहां पर जिस तरह से राघव ने शहनाज का ख्याल रखा, उसे देखकर फैंस को लगा कि इनके बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन इन बातों के बावजूद राघव और शहनाज एक-दूसरे को बस अच्छा दोस्त बताते हैं।

'टॉक्सिक' के मेकर्स ने कियारा आडवाणी को जन्मदिन पर दिया तोहफा? पोस्टर जारी कर लिखी प्यारी बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं। वह आज अपना 35वां जन्मदिन मना रही हैं। अभिनेत्री को सोशल मीडिया पर पहले से ही फैंस बधाई दे रहे हैं। इस बीच 'टॉक्सिक' के मेकर्स ने खास अंदाज में अभिनेत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। इसे मेकर्स की तरफ से उनका तोहफा माना जा रहा है।

'टॉक्सिक' के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'नादिया' के रूप में कियारा आडवाणी का एक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में अभिनेत्री लाल रंग के आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनकी गहरी नजर से लेकर उनके शीयर आउटफिट तक, पोस्टर में भरपूर ग्लैमर झलक रहा है।

'टॉक्सिक' की टीम ने अभिनेत्री की फोटो वाला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा 'हमारी नादिया को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई।'

इस पोस्ट पर फैंस तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 'जन्मदिन की बधाई, कियारा आडवाणी! आपको ढेर सारी खुशियां, ब्लॉकबस्टर सफलता और यादगार परफॉर्मेंस वाला एक और साल मिले। ऐसे ही चमकती रहें!' दूसरे ने लिखा, 'ऐसी आंखें जो सब कुछ कह देती हैं। जन्मदिन की बधाई।' कुछ लोगों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इस फिल्म के ट्रेलर की भी मांग की।

किसलिए फिल्म को कहा हां?

हाल ही में एक इंटरव्यू में कियारा ने बताया कि उन्होंने 'टॉक्सिक' के लिए हां क्यों कहा। उन्होंने फेमिना को बताया कि उन्हें हमेशा से गहरी कहानी और कई परतों वाले किरदारों में दिलचस्पी रही है। इसी बात ने उन्हें इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की ओर आकर्षित किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नादिया का किरदार बहुत अच्छे से लिखा हुआ और डिटेल में लगा।

दुबई में क्यों बस गए आर माधवन? बताई बड़ी वजह; कहा, 'मेरे सभी टैक्स भारत में भरे जाते हैं, मैं पहले भारतीय हूं'

कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?

अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा के अलावा नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं। कई बार टलने के बाद, यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

रानी पिंक सूट में शहनाज गिल ने ढाया कहर, वायरल एथनिक फोटोशूट ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री की चहेती अदाकारा शहनाज गिल अपने स्टाइल स्टेटमेंट और गजब के ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में शहनाज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया एथनिक फोटोशूट पोस्ट किया है, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया है।

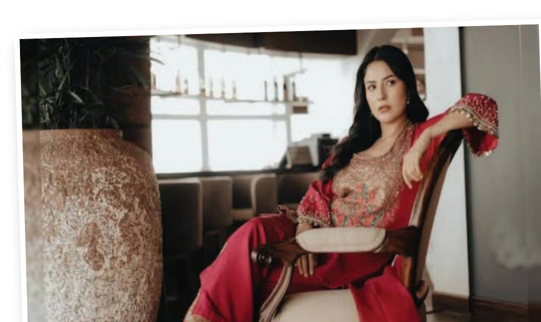

इस लेटेस्ट फोटोशूट में शहनाज ने गहरे रानी पिंक कलर का बेहद खूबसूरत एथनिक सूट कैरी किया है। उनके इस आउटफिट को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। कुर्ती के योक पर गोल्डन थ्रेडवर्क, बारीक गोटा-पत्ती और जटिल जरदोजी वर्क के साथ-साथ शानदार मिरर और सेक्विन वर्क किया गया है।

कुर्ती के डीप-नेकलाइन और स्लीव्स के किनारों पर लगे लटकन-मोती इस ड्रेस को एक रॉयल और हेरिटेज लुक दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाली स्ट्रेट-फिट एंकल लेंथ पैंट और नेट का एक खूबसूरत शीर दुपट्टा पेयर किया है, जो उनके पूरे लुक में एलिगेंस का तड़का लगा रहा है।

शहनाज गिल अपने ने मेकअप को बेहद सिंपल और सटल रखा है। उन्होंने लाउड कलर्स को छोड़कर न्यूड-ग्लॉसी लिप्स, न्यूड आईशैडो, मस्कारा से सजी पलकें और हल्का सा ब्लश ऑन चुना है, जो उनके नेचुरल फीचर्स को बखूबी उभार रहा है।

हेयरस्टाइल की बात करें तो शहनाज ने अपने सिग्नेचर स्टाइल को अपनाते हुए बालों को मिडल-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेवी लुक दिया है। उनके खुले काले बाल कंधों पर लहराते हुए उनके चेहरे के कट को बेहद खूबसूरती से फ्रेम कर रहे हैं।

शहनाज गिल का यह फोटोशूट किसी लग्जरियस इनडोर स्टूडियो का लग रहा है, जहां वह एक आलीशान विंटेज आर्मचेयर पर बैठकर बेहद दिलकश अंदाज में पोज दे रही हैं। तस्वीरों में शहनाज का आत्मविश्वास और उनका सेक्सी पोस्चर साफ झलक रहा है।

कभी वह चेयर पर रॉयल अंदाज में पीछे की ओर झुककर कैमरे में इंटेंस लुक दे रही हैं, तो कभी अपनी थिक-बॉर्डर वाली पैंट और गोल्डन हील्स को फ्लॉन्ट करते हुए फ्रंट पोज दे रही हैं। एक तस्वीर में वह अपने सिर को हाथों से थामे हुए गहराई से सोचती नजर आ रही हैं, जो उनके फैंस को काफी आकर्षित कर रहा है।

शहनाज के चेहरे का ग्लो और उनके सिजलिंग फेशियल एक्सप्रेशंस इस पारंपरिक आउटफिट में भी बोल्डनेस और ग्लैमर का परफेक्ट फ्यूजन पेश कर रहे हैं। शहनाज की इन तस्वीरों पर कमेंट बॉक्स में फैंस बॉम्बशेल, रॉयल क्वीन और ब्यूटी इन पिंक जैसे कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में इस पोस्ट पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com